RNI No. DELMUL/2012/47011

05 सितंबर, 2026 शनिवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 156

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

सबालेंका की यूएस ओपन में लगातार 16वीं जीत 07

संक्षिप्त वार्ता

जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे सीएम योगी, बोले- सनातन की आस्था मिटाने वाले खुद मिट्टी में मिल गए

मथुरा। देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे. जन्माष्टमी के अवसर पर सीएम योगी ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में गो-पूजन किया. इसके बाद उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि की कामना की.

मथुरा पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने सनातन आस्था, धार्मिक स्थलों के विकास और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. सीएम योगी ने कहा कि सनातन की आस्था को समाप्त करने के लिए इतिहास में कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी ताकत इसे मिटा नहीं सकी. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सनातन की आस्था को खत्म करने का प्रयास किया, वे स्वयं इतिहास में समाप्त हो गए.

भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं कष्ट सहे, लेकिन दूसरों के लिए प्रशस्त किया सुख-समृद्धि का रास्ता

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के नाम से भारत की पहचान दुनियाभर में बनी है। उन्होंने सृष्टि का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लिया। अपने जीवन में अनेकों कष्ट सहे और दुष्टों का संहार कर जनता के लिए सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान श्रीकृष्ण ने कारागार में जन्म लेने के बाद अपनी बाल्यकाल की लीलाओं से आमजन के कई कष्टों को मुस्कुराते हुए दूर किया। उन्होंने विश्व को संदेश दिया कि हमें मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण ने हमें कष्टों को दूर कर मार्ग निकालने की प्रेरणा दी है। उज्जैन में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में श्रीकृष्ण ने 64 कला और 14 विद्याएं सीखीं। श्रीकृष्ण के जीवन से हम सभी के लिए शिक्षा का महत्व प्रतिपादित होता है। सांदीपनि आश्रम में सुदामा जी के साथ उनकी मित्रता के प्रसंग हर काल में प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आख्यान पर्व के अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे।

36 हजार किमी ऊपर से जल, जंगल और जमीन पर नजर रखेगा उपग्रह

इसरो की कामयाबीः जीएसएलवी ने ईओएस-05 का किया सफल परीक्षण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी-एफ 17) के माध्यम से उन्नत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी ईओएस-05 का सफल प्रक्षेपण किया।

वेब वार्ता, श्रीहरिकोटा

यह भारत का पहला निर्दिष्ट इमेजिंग उपग्रह है जिसे लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू-तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ तालमेल बिठाते हुए, एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर लगातार नजर रख सकेगा।

वैज्ञानिकों ने इस उपग्रह को आसमान से नजर रखने वाली आंख बताया है, जो वास्तविक समय में उच्च-गुणवत्ता वाली तस्वीरें उपलब्ध कराएगा। ये तस्वीरें कृषि, जल संसाधन, वन प्रबंधन, खनिज पूर्वेक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश की सहायता करेंगी, जिससे राष्ट्रीय गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से तड़के 2 बजकर 55 मिनट पर निर्धारित समय पर उड़ान भरने के बाद, इस 2,367 किलोग्राम वजनी उपग्रह को सफलतापूर्वक उप-भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा में स्थापित किया गया। यह प्रक्षेपण करीब 18 मिनट तक चला और इसने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नया अध्याय जोड़ा। इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने सफल प्रक्षेपण की घोषणा करते हुए इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया।

उन्होंने कहा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जीएसएलवी-एफ17 यान ने उन्नत ईओएस-05 भू-इमेजिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। उन्होंने जानकारी दी कि यह श्रीहरिकोटा से 107वां प्रक्षेपण और जीएसएलवी का 19वां मिशन है। नारायणन ने जीएसएलवी की क्षमताओं में आए सुधार पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जीएसएलवी का पहला प्रक्षेपण (डीआई) 1,536 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह के साथ किया गया था, और तब से इसरो ने संरचनात्मक भार को अनुकूलित करने और प्रणोदन प्रणालियों में सुधार के जरिये जीएसएलवी के प्रदर्शन को धीरे-धीरे बेहतर किया है। आज, इसी लॉन्च यान का उपयोग करके 2,367 किलोग्राम वजनी सबसे भारी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया है। मिशन निदेशक थॉमस कुरियन ने बताया कि ईओएस-05 एक विशेष रूप से तैयार किया गया उपग्रह है, जो लगभग वास्तविक समय में तस्वीरें लेने में सक्षम है। परियोजना निदेशक इम्तियाज अहमद ने इसे अपनी तरह का अनूठा उपग्रह करार दिया, जिसमें कई बैंड में काम करने की क्षमता है।

उन्होंने कहा कि संरचना, सामग्री और क्षमता के लिहाज से यह एक जटिल उपग्रह है, जो भू-तुल्यकालिक कक्षा से देश के लिए अहम आंकड़े उपलब्ध कराएगा। बुधवार रात 11 बजकर 30 मिनट पर शुरू हुई 27 घंटे की उलटी गिनती सफलतापूर्वक पूरी हुई। सुबह का समय और हल्की बारिश भी लोगों के उत्साह को कम नहीं कर सकी, और बड़ी संख्या में लोग छाता लेकर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने पहुंचे।

इसरो की उपलब्धि को पीएम मोदी ने बताया भारत के लिए गर्व का पल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ईओएस-05 के सफल प्रक्षेपण और उसे निर्धारित कक्षा में स्थापित करने पर संगठन को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि को देश के लिए गर्व का पल बताया और इसे इसरो की एक और शानदार उपलब्धि करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बधाई संदेश में कहा कि जीएसएलवी-एफ17 द्वारा भारत के पहले इमेजिंग सैटेलाइट ईओएस-05 को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाने का सफल प्रक्षेपण, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं का स्पष्ट प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उद्योग की बढ़ती भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसरो और भारतीय उद्योग के बीच बढ़ती साझेदारी देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ताकत और विस्तार दे रही है, साथ ही पूरे अंतरिक्ष इकोसिस्टम में भारत की क्षमताओं को बढ़ा रही है। यह टिप्पणी देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की सरकार की नीति को भी रेखांकित करती है। इसरो ने भी अपनी ओर से सोशल मीडिया पर इस मिशन की सफलता की पुष्टि करते हुए लिखा, मिशन सफल! जीएसएलवी-एफ17 ने ईओएस-05 को तय कक्षा में स्थापित करके अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सफल लॉन्च के बाद इसरो प्रमुख डॉ. वी. नारायणन ने लोगों को संबोधित करते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जीएसएलवी-एफ17 यान ने एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ईओएस-05 (जियो इमेजिंग सैटेलाइट) को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है।

तेज रफ्तार से वाहन चलाना चालक की लापरवाही तय नहीं करती

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में तेज रफ्तार को एक सापेक्ष शब्द (रिलेटिव टर्म) बताया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी वाहन का तेज गति से चलना और किसी दुर्घटना में शामिल होना, यह अपने आप में यह साबित नहीं करता कि चालक लापरवाही या उतावलेपन से गाड़ी चला रहा था। न्यायालय ने यह फैसला 2009 के एक सड़क हादसे से जुड़े मामले में सुनाया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और एक टेंपो चालक को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें टेंपो चालक को बरी कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में मृतका का पुत्र ही एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी था। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि हाई स्पीड या ओवरस्पीड सापेक्ष शब्द हैं। अभियोजन पक्ष (प्रॉसीक्यूशन) के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसे ठोस सबूत पेश करे जिससे यह सिद्ध हो सके कि आखिर हाई स्पीड का वास्तविक

अर्थ क्या था। सिर्फ एक शब्द के आधार पर लापरवाही या उतावलेपन को लेकर कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि आपराधिक मुकदमे में अभियोजन को अपराध के प्रत्येक तत्व को साबित करना होता है, जबकि आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक उसका अपराध संदेह से परे सिद्ध न हो जाए। उच्च न्यायालय के इस फैसले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर तेज रफ्तार की कानूनी परिभाषा क्या है और क्या सिर्फ तेज गति होने से ही कोई चालक अपराधी बन जाता है।

इस 2009 के मामले में, एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और इसका आरोप एक टेंपो चालक पर लगा था। मामले की कई सालों तक सुनवाई चली और अंततः निचली अदालत ने टेंपो चालक को बरी कर दिया था। महिला के परिजनों ने इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों में मौजूद कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। न्यायालय ने कहा कि जब प्रत्यक्षदर्शी यह दावा कर रहा है कि टक्कर लगने के बाद वह सड़क पर गिर गया था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई, तो यह असंभव सा लगता है। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर गिरता है, तो कम से कम उसके शरीर पर खरोंच के निशान तो होने ही चाहिए। गवाह ने यह भी दावा किया था कि टेंपो ने साइकिल के बाईं ओर टक्कर मारी थी, लेकिन अदालत ने पाया कि अगर गवाह की बात मानी जाए तो टेंपो के दाहिने हिस्से पर डेंट आना चाहिए था, जबकि हल्का सा डेंट बाईं तरफ आया था।

श्रीनगर एयरपोर्ट पर पार्किंग के दौरान पोल से टकराया इंडिगो का विमान

नवी मुंबई से आ रही थी फ्लाइट

श्रीनगर। नवी मुंबई से श्रीनगर पहुंची इंडिगो की एक उड़ान शुक्रवार सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर पार्किंग के दौरान विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम (वीडीजीएस) के पोल के संपर्क में आ गई।

घटना में विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। एयरपोर्ट प्राधिकरण के अनुसार, घटना के बाद भी हवाईअड्डे का संचालन सामान्य रूप से जारी रहा।

विमान में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित

एयरपोर्ट प्राधिकरण के मुताबिक, इंडिगो की उड़ान संख्या 6ए 225 (वीटी-एनओजी) को सुबह करीब 9:02 बजे बे नंबर छह पर पार्क किया जा रहा था। इसी दौरान विमान वीडीजीएस पोल के संपर्क में आ गया। घटना के बाद विमान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित रूप से उतारा गया। इसके लिए मैनुअल एयरक्राफ्ट सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया। प्राधिकरण ने बताया कि घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के सही कारण का पता चल सकेगा।

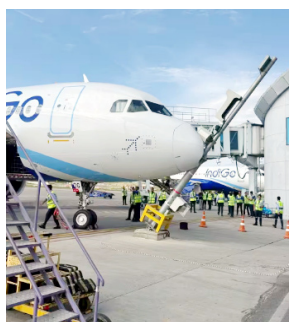

श्रीनगर एयरपोर्ट का होगा विस्तार

वहीं, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब और बड़ा होने वाला है। एयरपोर्ट के विस्तार पर 1,667 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके बाद यहां हर साल एक करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता हो जाएगी। नए टर्मिनल का काम 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से गृह मंत्रालय को दी गई जानकारी के अनुसार, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव के 1,667 करोड़ रुपये के प्रस्तावित विस्तार से सालाना यात्रियों को संभालने की क्षमता बढ़कर एक करोड़ होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

मित्र, आप अकेले नहीं... देश की 10 फीसद आबादी का कट चुका नाम

वेब वार्ता, नई दिल्ली। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम हटाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। चड्ढा ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए पंजाब सरकार और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। इस बीच पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर चड्ढा को इंगित करते हुए चुनाव आयोग की एनसीआर प्रक्रिया पर ही तंज कस दिया है।

चिदंबरम ने अपनी पोस्ट में कहा कि उन्होंने अपने मित्र राघव चड्ढा को ह्यभारत का गैर-मतदान नागरिकह्ण बनने पर बधाई दी है। उन्होंने आगे कहा कि चड्ढा अकेले नहीं हैं, बल्कि भारत की वयस्क आबादी के करीब 10 प्रतिशत लोगों को भी चुनाव आयोग ने गैर-मतदान नागरिक घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग की 13 अगस्त 2026 को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में राघव चड्ढा के नाम के सामने स्थायी रूप से स्थानांतरित यानी पीएस दर्ज किया गया है। उनका नाम पंजाब की एएसडीडी सूची में भी शामिल किया गया है। एएसडीडी में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट मतदाताओं को शामिल किया जाता है।

पंजाब में एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब तक 20.66 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए हैं। यह संख्या पुनरीक्षण से पहले राज्य के कुल मतदाताओं की करीब 9.7 प्रतिशत है। राघव चड्ढा ने मोहाली में दर्ज अपने वोटर आईडी का हवाला देते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनके नाम को मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया में राज्य के प्रशासनिक तंत्र और पुलिस का इस्तेमाल किया गया। चड्ढा ने सवाल उठाया कि उन्हें स्थानांतरित के तौर पर किसने चिह्नित किया, इस श्रेणी का सत्यापन किसने किया और इसे आगे किस स्तर पर प्रोसेस किया गया।

उनके मुताबिक, इन सभी प्रक्रियाओं में पंजाब सरकार के अधिकारी शामिल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर से लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर तक चुनावी प्रक्रिया में राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारी जुड़े रहते हैं। चड्ढा का आरोप है कि चुनावी ड्यूटी के बाद अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादले समेत करियर से जुड़े फैसले राज्य सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। इसी वजह से उन्होंने राजनीतिक दबाव और बदले की कार्रवाई की आशंका जताई है।

इस मामले ने पंजाब में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। एक ओर जहां चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण को चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की कवायद बताया जा रहा है, वहीं विपक्षी दल और कई नेता नाम हटाए जाने की प्रक्रिया और सत्यापन के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं।

काले बादल, तेज हवाएं और फिर जन्माष्टमी पर दिल्ली-एनसीआर में जमकर बरसे बदरा

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ले ली. दिन में तेज धूप और उमस के बीच करीब तीन बजे आसमान में तेजी से बादल छा गए. देखते ही देखते मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. अचानक हुई बारिश से कई इलाकों में मौसम सुहाना हो गया, वहीं लोगों को गर्मी और उमस से भी कुछ राहत मिली.

शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे दिल्ली और आसपास के इलाकों में आसमान पर काले बादल छा गए. कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश का दौर शुरू हो गया. मौसम में आए इस अचानक बदलाव ने लोगों को चौंका दिया. कई जगहों पर हवा की रफ्तार काफी तेज रही. मौसम विभाग के मुताबिक करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में लोगों को खुले स्थानों और कमजोर ढांचों के आसपास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग ने इससे पहले गुरुवार को ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई थी. विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार को भी पश्चिमी यूपी के अलग-अलग जिलों में तेज बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

पाकिस्तान सेना पर बड़ा हमला, 25 सैनिकों की मौत, बीएलए ने 2 जगह आर्मी को बनाया निशाना

वेब वार्ता, बलूचिस्तान

बीएलए ने पाकिस्तान सेना पर बड़ा हमला किया है. बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दो अलग-अलग हमले करने का दावा किया है. संगठन के मुताबिक, इन हमलों में 25 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए और तीन सैन्य वाहन नष्ट हुए.

BLA के प्रवक्ता जीयांद बलूच ने बताया कि पहला हमला जियारत क्रॉस के पास एक सैन्य काफिले पर किया गया. उनके मुताबिक, काफिले में चार वाहन थे, जिनमें से दो को निशाना बनाकर नष्ट

कर दिया गया. BLA ने दावा किया कि इस हमले में 18 जवान मारे गए, जबकि पांच घायल जवान वहां से भागने में कामयाब रहे. संगठन ने दावा किया कि हमले के बाद उसके लड़ाकों ने काफिले से हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए। इछअ के मुताबिक, इस कार्रवाई में उसकी फतेह स्क्वाड शामिल थी.

BLA ने जारी किया वीडियो

इछअ ने अपने मीडिया चैनल हक्कल पर 1 मिनट 11 सेकंड का एक वीडियो ट्रेलर भी जारी किया है. संगठन का दावा है कि इसमें जियारत क्रॉस हमले के दृश्य हैं. BLA ने कहा कि हमले का पूरा वीडियो बाद में जारी किया जाएगा.

हाजिका इलाके में हुआ दूसरा धमाका

दूसरे हमले को लेकर BLA ने बताया कि सुराब के हाजिका इलाके में उसके विशेष सामरिक अभियान दस्ते ने विस्फोटकों से लदे एक वाहन में दूर से विस्फोट किया. संगठन के मुताबिक, इस हमले में एक सैन्य वाहन नष्ट हुआ और 7 सैन्यकर्मी मारे गए. BLA ने कहा है कि इस कार्रवाई से जुड़ी और जानकारी उसके अगले साप्ताहिक बयान में दी जाएगी. पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से इन दावों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

संपादकीय

जवाब दे चुनाव आयोग

चुनाव आयोग और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) एक बार फिर चर्चा में नहीं, सवालों और विवादों में हैं। देश की राजधानी दिल्ली में करीब 47.5 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के राज्य महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। फिलहाल ड्राफ्ट सूची जारी हुई है। अभी लोगों के पास वक्त है कि वे आपत्ति और दावे दर्ज करा सकते हैं और मताधिकार के मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। दिल्ली में कुल मतदाता 1.45 करोड़ से अधिक थे, जिनमें से अब 97.53 लाख से कुछ अधिक ही नई सूची में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद में 47.85 फीसदी मतदाताओं के नाम पर लाल फेर दी गई है। ओखला, बदरपुर, कस्तूरबा नगर में भी 40-45 फीसदी मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली कोई सीमावर्ती क्षेत्र नहीं है, लिहाजा बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियों की संभावनाएं नगण्य हैं। जो बंगाली लोग दिल्ली में बसे हैं और वहां निरंतर काम कर रहे हैं, वे लंबे समय से दिल्ली में ही हैं। उनके मतदाता पहचान-पत्र भी बने हुए हैं और वे चुनावों में मतदान करते रहे हैं। दिल्ली में फरवरी-मार्च, 2025 में विधानसभा चुनाव हुए थे, संभवतः उन्होंने भी मतदान किया होगा, जिनके नाम अब एसआईआर में काट दिए गए हैं। जिन इलाकों में 40-47.8 फीसदी तक वोटर सूची से बाहर कर दिए गए हैं, वे भी विधानसभा क्षेत्र हैं, जाहिर है कि वहां भी वोट दिए गए होंगे और विधायक भी चुने गए हैं। क्या वे सभी फर्जी जन-प्रतिनिधि हैं? इसका जवाब तो चुनाव आयोग ही दे सकता है। उसने कुछ वर्गीकरण स्पष्ट किए भी हैं, लेकिन वे पर्याप्त और स्पष्ट नहीं हैं। काम या नौकरी के लिए कोई भी व्यक्ति बाहर जा सकता है। क्या उसकी अनुपस्थिति दिखा कर उसका मताधिकार छीना जा सकता है? महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव नवंबर, 2024 में हुए हैं।

वहां करीब 9.78 करोड़ मतदाताओं ने विधानसभा के लिए मताधिकार का प्रयोग किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 9 करोड़ से अधिक मतदाता थे, लेकिन अब एसआईआर के बाद ड्राफ्ट सूची में 7.71 करोड़ मतदाताओं के ही नाम दर्ज किए गए हैं। अर्थात 2.07 करोड़ मतदाता, किसी भी कारण से, फर्जी करार दे दिए गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र की घटनाएं, मताधिकार छीनने की कवायद, कोई सामान्य बात नहीं है। बेशक संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 326 में प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को मताधिकार का मौलिक अधिकार भी प्राप्त है। उसे चुनाव आयोग कैसे छीन सकता है? एसआईआर की अभी तक कवायद में 6 करोड़ से अधिक मतदाताओं का मौलिक अधिकार छिन चुका है। सरकार की तो आंखें मिची हैं, क्योंकि उसकी पार्टी चुनाव-दर-चुनाव जीत रही है। कमोबेश सर्वोच्च अदालत तो निर्णायक हस्तक्षेप करे और नागरिकों को इस संवैधानिक आघात से बचाए। यहां पश्चिम बंगाल का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है। वहां इसी माई, 2026 में विधानसभा चुनाव हुए हैं और भाजपा की पहली बार सरकार बनी है। चुनाव से पहले एसआईआर के तहत 27.16 लाख मतदाताओं को तार्किक विसंगति श्रेणी में रखा गया था। यह श्रेणी किसी अन्य राज्य में नहीं बनाई गई। बहरहाल सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर ट्रिब्यूनल गठित किए गए। बीते दिनों तक 82,782 मामले ट्रिब्यूनल ने निपटाए हैं, जिनमें से 75,443 मतदाताओं के नाम और दावे सही पाए गए। गौरतलब यह है कि मालदा, उत्तर 24 परगना सरीखे क्षेत्रों में 100 फीसदी नाम सही पाए गए, लेकिन वे मतदाता वोट नहीं डाल पाए। बंगाल में कुल 91 फीसदी मतदाता सही पाए गए, जिनके नाम काट दिए गए थे, लेकिन विडंबना है कि करीब 7 लाख लोगों ने ही आपत्तियां और अपने दावे दर्ज कराए हैं। शेष 20 लाख कथित मतदाता कौन हैं, वे कहां हैं, आपत्तियां दर्ज क्यों नहीं कराईं? गंभीर सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग जानता बूझकर है कि 6 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दे और यह देश के सामने स्पष्ट न हो कि इतने व्यापक स्तर पर संवैधानिक मताधिकार क्यों छीन लिए गए? बिंदुवार जवाब तो चुनाव आयोग ही दे सकता है। विपक्ष की कई पार्टियां इस मसले पर सवाल उठा रही हैं। लोकतंत्र में बेहतर यही होता है कि विपक्ष की आवाज को भी सुना जाए। चुनाव आयोग को यह भी प्रमाणित करना है कि उसने ये नाम दल विशेष की इच्छा पर नहीं हटाए हैं। चुनाव आयोग अगर यह प्रमाणित न कर पाया कि उसने सत्ता पक्ष के लाभ के लिए ऐसा नहीं किया है, तो उस पर लगे आरोपों को मजबूती मिलेगी। चुनाव आयोग को जल्द से जल्द इस मसले पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

बहुत गहरी हैं दलित विरोधी मानसिकता की जड़ें

उत्तराखंड के हल्द्वानी रामलीला मैदान में गत 8 अगस्त को कांग्रेस पार्टी द्वारा विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली को मुख्य रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया था। इसके बाद 11 अगस्त को उसी मंच पर श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास नाम के संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने मंच पर गंगाजल छिड़का, उसकी सफाई की और हवन,यज्ञ किया। इसे शुद्धिकरण आयोजन का नाम दिया गया । इसके बाद कांग्रेस ने इसे दलित अपमान के रूप में मुद्दा बनाया। स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुये भावुक होकर कहा कि इस शुद्धिकरण ने मुझे छुआछूत के डंक का अहसास कराया है और मेरा गहरा अपमान किया है। मैं एक दलित समाज से आता हूँ, इसलिए भाजपा विचारधारा के लोगों ने यह कृत्य किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इसे सीधे तौर पर दलित समाज का अपमान और संविधान विरोधी मानसिकता करार दिया। राहुल गांधी ने आरोपियों के खिलाफ रउ/रळ एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न शहरों व जिलों में कांग्रेस कार्यकताओं ने इस घटना के विरोध में जमकर प्रदर्शन किए और सचिवालय कूच किया। युवा कांग्रेस के कार्यकताओं ने दिल्ली के झंडेवालान स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकताओं ने मनुस्मृति की प्रतियां और उसके अनेक पन्ने जलाये। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है। एक विचारधारा बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान की है, जबकि दूसरी भाजपा और आरएसएस की है जो मनुस्मृति के आधार पर देश चलाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि खड़गे के भाषण के बाद मंच को अपवित्र मानकर गंगाजल से उसका शुद्धिकरण करना देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों,पिछड़ों व उनकी अस्मिता का अपमान है। नागपुर स्थित संघ के केंद्रीय मुख्यालय के बाहर भी मनुस्मृति जलाकर विरोध दर्ज कराया गया। गोया शुद्धिकरण की इस घटना को लेकर उपजा राजनीतिक विवाद इस समय देश के सबसे बड़े राजनैतिक मुद्दों में से एक बन गया है।

देश में इसतरह के कई ऐसे हाई प्रोफाइल मामले सार्वजनिक होते हैं जो संघ व भाजपा से जुड़े नेताओं की दलित विरोधी मानसिकता को उजागर करते रहते हैं। दलित कार्यकर्ता, लेखक और पत्रकार भंवर मेघवंशी को ही देख लीजिये। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में 1987 में आरएसएस की शाखा में जाना शुरू किया था। मेघवंशी संगठन में भीलवाड़ा के जिला प्रमुख के पद तक पहुंचे और 1990 के राम जन्मभूमि आंदोलन में एक सक्रिय कारसेवक के रूप में भी भाग लिया। परन्तु ऐसे समर्पित स्वयंसेवक को जातिगत भेदभाव के कारण हमेशा के लिए संघ से नाता तोड़ना पड़ा। संघ छोड़ने के मुख्य कारणों को उन्होंने अपनी चर्चित आत्मकथा मैं एक कारसेवक था में बयान किया है। उन्होंने लिखा है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान जब संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी उनके गृह जिले भीलवाड़ा (राजस्थान) आए, तो उन्होंने बड़े उत्साह से अपने घर पर भोजन तैयार करवाया। परन्तु संघ के वरिष्ठ सवर्ण नेताओं ने उनके घर आकर भोजन करने से यह कहते हुये साफ इनकार कर दिया कि वे समय की कमी के कारण भोजन पैक करवाकर साथ ले जा रहे हैं। बाद में संघ के उन्हीं सवर्ण नेताओं ने उनके घर का बना वह भोजन खाया नहीं, बल्कि उसे एक नाली में फेंक दिया। इस घटना से उन्हें यह एहसास हुआ कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले संगठन में आज भी छुआछूत और भेदभाव कायम है। उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव साँझा करते हुये लिखा कि आरएसएस के भीतर एक आंतरिक ब्राह्मणवादी पदानुक्रम काम करता है। दलित होने के कारण ही उन्हें संघ का प्रचारक बनने का दर्जा भी नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि संघ की शाखाओं और बौद्धिकों में अन्य धर्मों विशेषकर अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत का भाव भरा जाता है। उन्हें लगने लगा कि संगठन समाज को जोड़ने के बजाय वैचारिक रूप से विभाजित कर रहा है, जो उनकी खुद की अंतरात्मा को स्वीकार नहीं था। उन्हें यह एहसास हुआ कि संघ में रहकर जिस हिंदू राष्ट्र और समानता के दावे के लिए वे लड़ रहे थे, उसमें एक दलित के रूप में उनकी सामाजिक हैसियत को स्वीकार नहीं किया जा रहा था।

इन अपमानजनक घटनाओं और भेदभाव को इस तरह भी समझा जा सकता है कि गाँवों और अर्ध-शहरी इलाकों में दलितों को उनकी सामाजिक स्थिति का एहसास कराने के लिए कई अमानवीय प्रथाओं और पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरणतः कई राज्यों में दलित दूल्हे द्वारा शादी में घोड़ी चढ़ने या सज-धज कर बारात निकालने पर सवर्णों द्वारा हमले या पत्थरबाजी की जाती है। दलित युवाओं द्वारा मूंछ रखने, महंगे जूते पहनने, अथवा सवर्णों के सामने पैर पर पैर रखकर बैठने पर मारपीट और जानलेवा हमलों की घटनाएं प्रकाश में आती रही हैं। अनेक सार्वजनिक कुओं, हैंडपंपों, तालाबों या मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर आज भी हिंसक टकराव होते हैं। शिक्षण संस्थानों तक में दलित छात्र जातिगत पूर्वाग्रहों और अपमान का शिकार होते हैं। कई सरकारी स्कूलों में दलित बच्चों को भोजन की कतार में अलग बैठाने, उनके द्वारा बनाए गए भोजन को सवर्ण बच्चों द्वारा न खाने, या उन्हें अलग बर्तनों में खाना देने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कई बार दलित छात्रों को पढ़ाई के बजाय स्कूल या कॉलेज के शौचालय और परिसर साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है। आईआईटी,एम्स,और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों या सहपाठियों द्वारा योग्यता पर सवाल उठाने और जातिसूचक टिप्पणियों के कारण कई मेधावी दलित छात्रों को आत्महत्या तक के लिए मजबूर होना पड़ा है। दलित महिलाएं लैंगिक और जातिगत दोनों स्तरों पर दोहरे शोषण का शिकार होती हैं। हाथरस और खैरलांजी जैसी ऐतिहासिक और भयावह घटनाओं से लेकर रोजमर्रा की अनेक घटनाओं तक, दलित महिलाओं को डराने, दबाने और पूरे दलित समुदाय को सबक सिखाने के लिए यौन हिंसा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आम मामलों की तुलना में दलित महिलाओं के साथ हुए यौन अपराधों में दोषियों को सजा मिलने की दर बेहद कम अर्थात करीब 2% से भी कम रहती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर पुलिस और व्यवस्था में रसूखदार लोगों का प्रभाव होता है। उचित मजदूरी मांगने या अपनी जमीन पर दावा ठोकने पर दलित बस्तियों पर हमले, आगजनी और उनके घरों को फूंकने की सामूहिक हिंसा तमिलनाडु व बिहार के कई ऐतिहासिक मामले में देखी गई है। सवर्णों की बात न मानने या उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराने पर पूरी दलित बस्ती का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। इस तरह के तमाम हालात इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये पर्याप्त हैं कि हमारे देश में दलित विरोधी मानसिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं।

लेखिका- निर्मल रानी

(यह लेखिका के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

एम्स में तारीख पर तारीख का खेल, 13 साल नहीं हो पाया ऑपरेशन

एम्स जैसे संस्थान में 13 वर्षों में एक बच्ची का ऑपरेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण उसकी जान चली गई। यह मामला सामने आने के बाद भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था और भारत में जिनके पास व्यवस्था की कमान है, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर एक नया सवाल खड़ा हो गया है। कोटा की 15 वर्षीय बच्ची तन्वी को उसके पिता 2014 में एम्स लेकर गए थे। वहां पर जांच के बाद कहा गया, इसे जन्मजात हृदय की बीमारी है। इसका ऑपरेशन करना होगा। इसके बाद इलाज के लिए पिता ने डेढ़ लाख रुपए 2 सितंबर 2015 को जमा कर दिए थे, जो एम्स ने मांगे थे। उसके बाद भी 2026 तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। हर बार नई तारीख पर तारीख मिलती रही। अंततोगत्वा बिना ऑपरेशन के तन्वी की मौत हो गई। 13 साल तक लगातार कोटा से दिल्ली जाना एम्स में बच्ची को भर्ती कराना, बार-बार पैसे खर्च करना, बच्ची की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी उसके बाद भी उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। शायद पिता की गलती यह हुई कि

उसने अपनी बच्ची का ऑपरेशन समय पर हो जाए इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में भी तीन बार गुहार लगाई, लेकिन जैसा भारत में होता है गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग व्यवस्था और नियम कानून होते हैं। यही इस गरीब के साथ हुआ। 2015 में डेढ़ लाख रुपए जमा कर दिए थे, उस समय उतने ही पैसे मांगे गए थे।

पिछले 13 सालों में लाखों रुपए उसके पिता ने बच्ची के इलाज के नाम पर खर्च किए, लेकिन कोई उपचार तो हुआ नहीं उल्टे हर बार उसे एक नई तारीख पर तारीख मिलती रही। दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल अपनी विशेष चिकित्सा सुविधा के लिए भारत से लेकर सारी दुनिया में जाना जाता है। यहां पर बड़े-बड़े व्हीव्हीआईपी का इलाज भर्ती होते ही शुरू हो जाता है, लेकिन गरीबों की कितनी बड़ी दुर्दशा है यह तन्वी के मामले से उजागर होती है। बार-बार लाइन पर लगो, जांच के लिए बार-बार एम्स में बुलाया जाता है। अलग-अलग तारीखें दी जाती हैं। मरीज का भाग्य है कि जरुरत के समय पर इलाज मिल जाए और डॉक्टर भगवान बन जाएं। इस केस में तो यही कहा जा सकता है। भगवान ने इसकी जितनी उम्र लिखी थी, जितने कष्ट उसके लिए लिखे थे, वह सब भोगकर वह भगवान के पास चली गई है। डॉक्टर कर भी क्या सकते हैं। मरीजों की गलती है कि वह डॉक्टर को भगवान मानते हैं। भारत के सरकारी अस्पतालों में इलाज को लेकर पहले से ही लोगों में एक धारणा जो बनी हुई है, उसके मुताबिक अस्पताल तो खोल दिए जाते हैं, लेकिन मरीजों के हिसाब से डॉक्टर और अन्य स्टॉफ नहीं होता। यदि किस्मत से चिकित्सक उपलब्ध हो भी गए तो जांच के लिए उपकरण और मशीनें नहीं होतीं। मान लें कि यदि मशीनें और अन्य उपकरण भी अस्पताल में मौजूद हैं तब भी दबाओं का टोटा हो जाता है। ऐसे में मरीज के लिए सरकारी अस्पताल में समय पर उचित इलाज करा लेना टेड़ी खीर साबित होता है। एम्स के मौजूदा मामले ने इस धारणा को कहीं न कहीं मजबूत करने का ही काम किया है। यह अलग बात है कि एम्स में वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है, जिस पर आए दिन चर्चा तो होती है, लेकिन समाधान की ओर एक कदम भी आगे बढ़ता हुआ कोई नहीं दिखता है। एम्स जैसे माने हुए अस्पताल में एक बच्ची का समय पर इलाज न हो पाना, और उसकी दर्दनाक मौत हो जाना अपने आप में अस्पताल के लिए भी शर्म की बात है। वहीं दूसरी तरफ बच्ची का पिता डॉक्टर को भगवान मानकर अब रोता हुआ फिर रहा है। कह रहा है कि हम 13 साल में अपनी बच्ची का इलाज नहीं करा पाए, जिसको लेकर वह दुखी है। इसके अलावा और वह कुछ कर भी नहीं सकता है। एम्स हॉस्पिटल दिल्ली को अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव करने की जरूरत है। यदि मरीज के तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता है या समय रहते यदि 13 साल तक ऑपरेशन की डेट पर डेट मिलती रही लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

लेखक- सनत जैन

जोखिम यात्रा में वाहन बीमा की प्रासंगिकता

प्रदेश में वैध बीमा बगैर संबंधित वाहन को अब ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके तहत पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे, जिन्हें केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाएगा। हाल ही में उच्चनतम न्यारयालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और पीके मिश्रा की युगल पीठ ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुपालन में कमी को उजागर करने वाली अपील की सुनवाई करते हुए इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) और आईआरडीए (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) के माध्यम से लागू करने के निर्देश दिये।

बिना बीमा या बिना पंजीकरण वाले वाहनों की पहचान के लिए बीमा सूचना ब्यूरो (आईआरडीए के तहत स्थापित)हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्य म से वाहन पोर्टल डेटा की प्रक्रिया आरंभ की जायेगी । इससे सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों राहत सहित मुआवजा सुनिश्चित में मदद मिलेगी। इस परिप्रेक्ष्य। में नई कारों के लिए बीमा अवधि को चार साल और नए दुपहिया वाहनों के लिए छह साल का तृतीय-पक्ष बीमा खरीदने के लिए न्यायालय ने इरडा को आवश्यतक निर्देश दिया।। अदालत ने कहा कि वर्तमान में, राजमार्गों और सड़कों पर तैनात एएनपीआर कैमरों में तेज गति, लाल बत्ती जंप करना, सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाने गाड़ी चलाते समय मादक पदार्थ सेवन, पूर्ण नींद न लेना, मोबाइल उपयोग, सीटबेल्ट हेलमेट की उपेक्षा पर नियंत्रण के लिए मानक कैमरो का उपयोग किया जाये। सड़कों पर पशुओं के कारण होने वाले हादसों को रोकने ग्राम व वार्ड स्तर पर समितियां बनेंगी। इन समितियों को प्रोत्साहन राशि देकर एक्टिव किया जाएगा प्रदेश में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या करीब 1.75 करोड़ है। इनमें से करीब 35% (करीब 61 लाख) वाहन बिना वैध इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। उल्ल्खनीय है कि सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा शून्य पर लाने के मकसद से संचालित जीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का दायरा 6 से बढ़ाकर 9 जिलों तक कर दिया है। पहले से शामिल धार, सतना, रीवा, सागर, जबलपुर और खरगोन के साथ अब भोपाल, इंदौर और उज्जैन भी इसमें जुड़ गए हैं। प्रौद्योगिकी को अपनाने से सड़क सुरक्षा में क्रांति आ सकती है। बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणालियाँ, निगरानी कैमरे और स्मार्ट सिग्नलिंग यातायात के सुचारू प्रवाह में योगदान कर सकते हैं और यातायात नियमों की निगरानी और उन्हें लागू करने में सहायता कर सकते हैं।

सड़क सुरक्षा को मुख्य रूप से सड़क की स्थिति, वाहन की गुणवत्ता और पर्यावरण संबंधी कारक प्रभावित करते हैं। भारत में कई सड़कों में अच्छी तरह से बनाए रखी गई सतहों और स्पष्ट संकेतों सहित उचित बुनियादी ढांचे का अभाव है। पैदल यात्री-अनुकूल मार्गों का अभाव जोखिमों को और बढ़ा देती है, जिससे पूरे देश में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कानून प्रवर्तन को मजबूत करना, उल्लंघनों के लिए सख्त दंड के साथ मिलकर, एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है और अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है। भारत में सड़क सुरक्षा एक बहुआयामी चुनौती है जिसके लिए व्यापक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है । इसमें बेहतर बुनियादी ढांचे से लेकर जिम्मेदार सड़क उपयोग की ओर सांस्कृतिक बदलाव व सुरक्षित सड़क निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह सिर्फ हमारे गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है; अपितु सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने से संबंधित है ।

हालाँकि देश में सड़क सुरक्षा कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है। जिस देश में रैली, राजनीतिक धरना, रोड शो, उपकृत करने हेतु अनावश्याक निर्माण सहित नागरिकों के जन्मच से लेकर मत्युं तक समस्तै आयोजन सड़क पर होते हों वहां मौतों का आंकड़ा शून्य पर लाने की धारणा गले नहीं उतरती। कोहरा, बारिश, घटियानिर्माण ।,ओवरलोड़िग, ओवरटेकिंग, भ्रष्टोचार भी इसके लिए कम जिम्मोदार नहीं हैं। वर्तमान में विविध श्रेणी में बन रहे नित नवीन मार्ग के बावजूद घंटों जाम की स्थिति क्याट आगामी 50 वर्षों की नीति का प्रमाप बन सकती है। जहां एक ही बारिश पूरे तंत्र की पोल खोलने का माद्दा रखती हो वहां सुरक्षा की गारंटी महज एक छलावा है। सुरक्षित यातायात व्यमयसाध्यत निर्मित भंगार होते कैमरे- सिंगनल, धंसकती सीवेजलाइन, आकार लेते गड्ढे, बेतरतीब तार, क्रीड़ास्थाली व पशु पनाहगार बने सडकों पर पुलिस वसूली का शिकार होते यात्री की सुरक्षा को न्यालयालय किस तरह देखेगा जिसकी आंखों के सामने पीडि त को नियत तारीख की कीमत चुकानी पड़ती है। इसके लिए अनिवार्य बीमा कहीं बीमा कंपनियो के अनुचित लाभ का माध्यंम मात्र बनकर न रह जाये इसलिए उस पर अंकुश जरूरी है। वैध बीमा पश्चोात भी पीड़ितों को प्राय: उसके लाभ से वंचित होने की बानगी अक्सेमर देखने को मिलती है चाहे वह बीमा का कोई भी क्षेत्र हो। ऐसे समय में जब देश को शक्कयर, ईधन, बस भाड़े खाद्य सामग्री सहित अनेक मूलभूत आवश्यंकताओं के लिए अचानक दोगुनी मंहगाई मार की त्रासदी से गुजरना पड़ रहा हो ऐसे समय में अनिवार्य बीमा को तत्कानल लागू करने का निर्णय न्याकयसंगत नही जान पड़ता।

लेखक – राकेश कुमार वर्मा

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

आलेख

तेजी से बदल रही है भारत की तस्वीर

भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों, टाटा, बिरला, रिलायंस, अडानी, आदि को अपना व्यवसायिक साम्राज्य खड़ा करने में दशकों लग गए थे। इन समूहों को अपनी सम्पत्ति को 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचाने में लगभग 30 वर्षों का समय लगा था परंतु आज के युवावर्ग द्वारा स्थापित की जा रही कम्पनियों को अपनी सम्पत्ति को 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंचाने में केवल 1 से 3 वर्ष का समय लग रहा है। भारत में समय बहुत तेजी से बदल रहा है और भारतीय युवा आज भारत की तस्वीर बदलने को उतावाले होते दिखाई दे रहे हैं। जून 2026 में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स) का व्यवसाय करने वाली सर्वम कम्पनी ने अपनी स्थापना के केवल 3 वर्ष के अंदर ही 150 करोड़ (1.5 बिलियन) अमेरिकी डॉलर की सम्पत्ति खड़ी कर ली है। इसी प्रकार, आज जेप्टो एवं मेन्सा नामक ब्राण्ड कुछ ही महीनों में व्यवसाय के उस स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हासिल करने में पुरानी बड़ी कम्पनियों को कई दशक लग गए थे। आज के समय में टेक्नॉलोजी के क्षेत्र में स्थापित हो रही कम्पनियों की तुलना यदि इसी क्षेत्र में लगभग 20/25 वर्ष पूर्व स्थापित कम्पनियों से भी की जाय तो सम्पत्ति खड़ी करने के समय में बहुत अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। वर्ष 2000 में स्थापित कम्पनियों को यूनिकोन (100 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सम्पत्ति बनाना) बनने में लगभग 20 वर्ष से अधिक का समय लग रहा था, वहीं वर्ष 2020 में स्थापित कम्पनियों को यूनिकोन बनने में केवल एक वर्ष का समय लग रहा है। वित्तीय क्षेत्र में स्थापित की गई कम्पनियों को यूनिकोन बनने में 30 वर्ष का समय लगा है। वहीं मेन्सा ब्राण्ड जैसी कम्पनी को यूनिकोन बनने में केवल 6 माह का समय लगा है। बाजार वही है, परंतु समय तेजी से बदल रहा है। इस परिवर्तन में भारतीय युवाओं की प्रमुख भूमिका रही है। आज भारत में व्यावसायिक घराने/खानदान एवं अमीर लोग कहीं पीछे छूट गए हैं एवं युवा पीढ़ी तेजी से बिलिनायर की सूची में अपनी जगह बना रही है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में एक लाख से अधिक नए स्टार्ट-अप स्थापित हुए हैं। आज भारत ने अपने आप को, अमेरिका एवं चीन के बाद, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट-अप इको सिस्टम में स्थापित कर लिया है। भारत में आज अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता उत्पादों को बढ़ावा देने वाले स्टार्ट अप बन रहे हैं। किराना उत्पादों से संबंधित ऐप अधिक संख्या में बनाए जा रहे हैं क्योंकि यूपीआई जैसा पेमेंट गेटवे पूर्व से ही उपलब्ध है और भुगतान

प्रणाली को अलग से विकसित करने की आवश्यकता ही नहीं है। साथ ही, 140 करोड़ नागरिकों का बायोमेट्रिक डाटा पहिले से ही सत्यापित है और यह उपभोक्ता उत्पादों से सम्बंधित ऐप बनाने वाले इंजीनियरों को उपलब्ध भी है। भारत में डिजिटल लाकर में 750 करोड़ से अधिक दस्तावेज जमा हो चुके हैं। सस्ता इंटरनेट डाटा उपलब्ध है एवं 90 करोड़ से अधिक भारतीय इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इन परिस्थितियों के बीच आज 20 वर्ष के युवा एंटरप्रेन्योर को व्यवसाय स्थापना के प्रथम दिवस से ही पूरा भारत उसके उत्पाद के बाजार के रूप में उपलब्ध है। उक्त कारकों के चलते ही वर्ष 2021 में भारत में 45 नए यूनिकोन विकसित हुए थे।

भारत के पास आज दुनिया के सबसे स्मार्ट एवं कुशल इंजीनीयर तो हैं परंतु हमारे पास अपने गूगल, अपना यू ट्यूब एवं अपना फेस बुक नहीं है। क्योंकि, भारत में उच्च स्तर का तकनीकी नवाचार नहीं हो पा रहा है जिससे उच्च तकनीकी के ऐप भारत में कम बन रहे हैं। हालांकि, विकसित देशों में जो भी उच्च स्तर के तकनीकी नवाचार हो रहे हैं इनमें भारतीय इंजिनीयरों की भी महती भूमिका रहती है। इसी कारण से भारतीय इंजीनियरों की विकसित देशों में भारी मांग है। भारतीय युवाओं को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने के स्थान पर भारत में उच्च तकनीकी के नवाचार करने की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। अब तो विकसित देश भी यह मानने लगे हैं कि वर्तमान सदी केवल भारत की है। कई विकसित देशों सहित चीन में जनसंख्या वृद्धि दर अब ऋणात्मक हो चुकी है। साथ ही, इन देशों में वृद्ध नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पूरे विश्व में आज भारत एक युवा देश के रूप में उभर रहा है। अत: भारतीय युवाओं से न केवल भारत में आर्थिक विकास को गति देने बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की अपेक्षा की जा रही है। कई देशों ने तो अपनी संसद में प्रस्ताव पास करने के उपरांत भारत सरकार से भारतीय युवाओं को इन देशों में भेजने की मांग की है।

भारतीय युवा आज न केवल भारत में तेजी से यूनिकोन विकसित कर रहा है बल्कि आज भारतीय अन्य देशों में पहुंच कर अपने व्यापार का विस्तार भी कर रहे हैं, इसी कारण से आज प्रतिवर्ष भारत से लगभग 7 लाख नागरिक विभिन्न देशों में जाकर बस रहे हैं। श्री लक्ष्मी मित्तल ने ब्रिटेन में आरसेलोर स्टील कम्पनी खरीद ली है। यह कम्पनी पूर्व में बीमार कम्पनी की श्रेणी में शामिल थी परंतु मित्तल समूह ने इसे आज विश्व की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कम्पनी बना दिया है। इसी प्रकार वर्ष 2008 में टाटा समूह ने जैग्वार एवं लैंड रोवर कम्पनी को खरीद लिया था। भारतीय मूल के नागरिक आज ब्रिटेन में जायदाद निवेशकों के क्षेत्र में सबसे बड़े निवेशक माने जा रहे है। यूरोप में आज भारतीय कम्पनियां सबसे अधिक राशि का निवेश करती हुई दिखाई दे रही हैं और यूरोपीयन कम्पनियों का अधिग्रहण कर रही है। अमेरिका में भी लगभग यही स्थिति है। अमेरिका में सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक कम्पनी को भारतीय ने खरीद लिया है। इसी प्रकार, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अडोबी जैसी बड़ी कम्पनियों को भारतीय मूल के नागरिक ही चला रहे हैं। भारतीय मूल के ही श्री अजय बांगा आज विश्व बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बन गए हैं। भारत में आज 15 लाख इंजिनीयर प्रतिवर्ष बन रहे हैं। विश्व के लगभग समस्त देशों को आज भारतीय युवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। विशेष रूप से जापान एवं यूरोपीयन देशों में प्रौढ़ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चीन से आज कई देश दूर भाग रहे हैं क्योंकि चीन ने विभिन्न देशों को कर्ज दे रखा है, यदि कोई देश इस कर्ज का भुगतान समय पर नहीं कर पाता है तो चीन उस देश के संसाधनों पर अपना अधिकार जताने लगता है। इससे इन देशों के साथ चीन के सम्बंध अच्छे नहीं रहे हैं। दूसरी ओर भारत में राजनैतिक स्थिरता है, जिसके चलते आज भारत के विश्व के लगभग समस्त देशों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बंध हैं। भारत आज विश्व के कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते सम्पन्न कर रहा है। आज स्थिति यह निर्मित हो रही है कि भारतीय यूनिकोन अमेरिकी कम्पनियों का अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत आज जापान, इजराईल, रूस, यूएई एवं अमेरिका जैसे देशों का रणनीतिक साझीदार है। साथ ही, भारत के सम्बंध अब चीन के साथ भी सामान्य हो रहे है। भारत आज वैश्विक दक्षिणी क्षेत्र की आवाज बन रहा है क्योंकि विश्व के कई देशों का अब चीन पर भरोसा नहीं रहा है। भारत आज जी-20 देशों के समूह का भी सदस्य है, तो जी-7 देशों के समूह एवं वैश्विक दक्षिणी क्षेत्र के बीच एक पुल का काम करता हुए भी दिखाई दे रहा है। भारत एससीओ का भी सदस्य है तो ब्रिक्स का भी सदस्य है। साथ ही, भारत क्वाड का भी सदस्य है। इस प्रकार, भारत आज विश्व के लगभग समस्त महत्वपूर्ण समूहों का सदस्य है एवं भारत के विश्व के लगभग समस्त देशों के साथ बहुत अच्छे, सौहार्दपूर्ण, व्यावसायिक एवं व्यावहारिक सम्बंध हैं। इसी कारण से ही कुशल भारतीय युवाओं की मांग आज पूरे विश्व में कई देशों द्वारा की जा रही है।

लेखक – प्रहलाद सबनानी

(सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

वाई-वाई नूडल्स कंपनी की भुजिया की बिक्री पर भारत में लगाई रोक

नई दिल्ली। मैगी और यिप्पी के अलावा आपने एक और नूडल्स का नाम सुना होगा। वाई-वाई नूडल्स। वाई-वाई नूडल्स नेपाल के सबसे अमीर शख्स बिनोद चौधरी की मल्टी-इंडस्ट्री कंपनी सीजी कॉर्प ग्लोबल का ब्रांड है। अब इसी कंपनी पर भारत में संकट आ गया है। शुक्रवार को भारत ने वाई-वाई नूडल्स बनाने वाली कंपनी को कुछ प्रोडक्ट्स की बिक्री रोकने का आदेश दिया गया है। जांच में पता चला कि कंपनी अपनी फैक्ट्री में भारतीय स्नैक्स बनाने के लिए साफ-सफाई का ध्यान रखे बिना फर्श पर गिरे और टूटे हुए नूडल्स का इस्तेमाल कर रही थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाई-वाई नूडल्स पर ये एक्शन भारत में फूड सेफ्टी को लेकर चलाए जा रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा है। इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी डोमिनोज और पिज्जा हट से लेकर डियाजियो जैसे बड़े और छोटे ब्रांड्स और खाने-पीने की जगहों के खिलाफ फूड सेफ्टी, साफ-सफाई या लेबलिंग में किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर सख़्त कार्रवाई कर रहे हैं।

चीनी के दाम में 20फीसद गिरावट, त्याहारों पर लोगों को मिल सकती है राहत

नई दिल्ली। आने वाले त्योहारों पर चीनी के दाम और गिरने की उम्मीद बढ़ गई है। डिपॉर्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक्स पर पोस्ट करके चीनी के सस्ता होने की जानकारी दी है। पोस्ट के मुताबिक देश के खुदरा बाजार में चीनी के दाम करीब 5फीसदी तक कम हो गए हैं। इससे पहले चीनी की एक्स-मिल कीमतों में करीब 20फीसदी की बड़ी गिरावट आई है। अगर चीनीमंडी के आंकड़ों की बात करें तो गुरुवार शाम को अपडेट किए गए रेट के मुताबिक चीनी के दाम 61 रुपए किलो तक आ गए हैं। दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, रांची में 3 सितंबर को चीनी 61 रुपए में बिकी। गुवाहटी, कानपुर और रायपुर में 62 रुपए किलो थी और चेन्नई में 63 रुपए।

सरकार का कहना है कि एक्स-मिल कीमतों में गिरावट का असर अब धीरे-धीरे खुदरा बाजार में दिखाई देने लगा है और आने वाले दिनों में चीनी के दाम और गिर सकते हैं।

'72 घंटे में गिरफ्तार होगा स्वतंत्र', सीजेपी की मांग दिल्ली पुलिस को मंजूर

सांसद चंद्रशेखर बोले- निशु को मिले न्याय

नई दिल्ली, 04 सितंबर (वेब वार्ता)। कॉकरेच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शुक्रवार को दिल्ली में संसद मार्ग थाने पर धरना दिया है। सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका अपने समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और निशु के लिए न्याय की मांग की। सांसद चंद्रशेखर आजाद भी सीजेपी के समर्थन में पहुंचे हैं।

दिल्ली पुलिस ने मान ली मांग

सीजेपी की निशु आजाद के वकील, अक्ळउ लॉ डिपार्टमेंट के ऋषव रंजन ने बताया कि आज पुलिस के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में एडिशनल DCP मंजीत शर्मा की मौजूदगी में हमने मौजूदा एफआईआर में हत्या की कोशिश, क्रिमिनल धमकी और रउ/रळ एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ने की मांग की हैं।

ऋषव रंजन के अनुसार, पुलिस हमारी मांग के लिए मान गई है। हमने मांग की है कि निशु को दी जा रही ऑनलाइन धमकियों के खिलाफ एक अलग ऋक्षफ्रदर्ज की जाए। दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि वे उसे (स्वतंत्र भारद्वाज) आज या 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर सकते हैं। हमने उन अकाउंट्स की लिस्ट दी है, जिनके जरिए निशु को ऑनलाइन गालियां दी जा रही हैं।

सीजेपी नेताओं का कहना है कि जब स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वे धरने से नहीं उठेंगे। उनका कहना है कि वे निशु आजाद और उनके पिता संजय को न्याय दिलाकर रहेंगे।

CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका, इंडियन यूथ कांग्रेस दिल्ली के प्रेसिडेंट अक्षय लाकड़ा ने पुलिस से मिलकर अपनी मांग रखी है कि उखढ नेता निशु आजाद और उनके पिता संजय के मामले में दर्ज रिपोर्ट में हत्या की कोशिश, SC/ST एक्ट और POCSO की धाराएं जोड़ी जाएं। बता दें कि सीजेपी नेताओं के साथ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है।

'एक भी पात्र मतदाता का नाम नहीं कटेगा'

दिल्ली मतदाता सूची पर सीईओ ने दिलाया भरोसा

नई दिल्ली, 04 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जारी मसौदा मतदाता सूची को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाताओं को राहत देते हुए भरोसा दिलाया है। कार्यालय ने जारी बयान में कहा कि एक भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं कटेगा। घर-घर सत्यापन के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे मतदाताओं को एएसडीडी श्रेणी में चिह्नित किया गया है।

30 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं आपत्तियां

सीईओ ने आगे कहा, गणना प्रपत्र उपलब्ध न होने वाले मामलों को मृत्यु, अनुपस्थित/अनट्रेसेबल, स्थाई रूप से स्थानांतरित, पहले से नामांकित और अन्य पांच श्रेणियों में रखा गया है। जिन मतदाताओं का नाम छूट गया है, वे 30 सितंबर तक दावे-आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से उठाई गई आपत्तियों और चिंताओं का भी जवाब दिया है। दोनों को अलग-अलग पत्र के माध्यम से उनके हर सवाल का जवाब आयोग ने विस्तार से दिया है।

एटीएस-एनआईए अधिकारी बनकर रिटायर्ड कर्मचारी को डराया, 30 लाख की ठगी

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के फतेहाबाद निवासी सुनील सिंगला को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के फतेहाबाद निवासी सुनील सिंगला को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी पर फर्जी पहचान के जरिए लोगों को डराने, आपराधिक धमकी देने और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप लगें हैं। वहीं इस मामले के सामने आने से एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लेकर लोगों को सतर्क रहने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

इस मामलें के बारे में बताए तो यह ई-एफआईआर नंबर 60001459/2025 (FIR नंबर 47/25) से जुड़ा है जो 9 दिसंबर 2025 को इठर की संबंधित धाराओं के तहत क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारका दिल्ली में रहने वाले भारतीय रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। इसको लेकर पुलिस ने बताया है कि साइबर ठगों ने पीड़ित से संपर्क कर अपनी असली पहचान छिपाई और खुद को ATS, NIA और RBI के अधिकारी के तौर पर पेश किया। इसके बाद उन्हें गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी गई थी।

83 करोड़ की साइबर ठगी, थाईलैंड से दुबई भागा मास्टरमाइंड

एलओसी की मदद से एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस ने दबोचा

नई दिल्ली, 04 सितंबर (वेब वार्ता)। द्वारका जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने साइबर ठगी की रकम को फर्जी कंपनियों और म्यूल बैंक खातों के जरिये अलग-अलग खातों में घुमाने वाले अंतरराज्यीय साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, जांच में अब तक अलग-अलग राज्यों में दर्ज 89 साइबर ठगी की शिकायतों का इस सिंडिकेट से संबंध सामने आया है। इन शिकायतों में ठगी की कुल रकम करीब 83 करोड़ 23 लाख 70 हजार 547 रुपये है। पुलिस ने समयबद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 14 लाख 84 हजार 394 रुपये की रकम होल्ड भी कराई है।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान चेतन सहरावत, शक्ति गुर्जर, धर्मेंद्र कुमार, तरुण, दीपक और गौरव कादियान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक चेतन सहरावत सिंडिकेट का मुख्य हैंडलर था और अन्य आरोपित उसके निर्देश पर काम करते थे। मामले में दो आरोपितों को लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) की मदद से एयरपोर्ट पर पकड़ा गया।

एनसीआरपी पर मिला संदिग्ध खाता

पुलिस के मुताबिक साइबर वित्तीय ठगी से जुड़ी शिकायतों का राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर विश्लेषण किया जा रहा था। इसी दौरान द्वारका सेक्टर-23ए स्थित यस बैंक के एक संदिग्ध खाते का पता चला। जांच में सामने आया कि तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत अलग-अलग राज्यों में दर्ज साइबर ठगी की शिकायतों की रकम इस खाते में पहुंची थी।

इसके बाद पुलिस टीम ने बैंक खातों में हुए लेनदेन, खाताधारकों और उनसे जुड़ी फर्मों की जानकारी का विश्लेषण किया। जांच आगे बढ़ने पर उन लोगों की पहचान हुई जो इन खातों और कंपनियों का इस्तेमाल ठगी की रकम को प्राप्त करने, स्थानांतरित करने और नकदी निकालने के लिए कर रहे थे। इस आधार पर छह आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि सिंडिकेट से जुड़े लोग अलग-अलग नामों से बैंक खाते और फर्म खुलवाते थे। पुलिस के अनुसार, कई म्यूल खाते भोले-भाले लोगों को नौकरी देने या वेतन खाता खुलवाने का झांसा देकर खुलवाए गए थे। बाद में इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से प्राप्त रकम को दूसरे खातों में स्थानांतरित करने और उसे निकालने के लिए किया जाता था। आरोपितों ने पुलिस को बताया कि कुछ सह आरोपितों की मदद से विभिन्न बैंकों में खाते और कंपनियां खुलवाई गई थीं।

सोनम वांगचुक के 'ये संत नहीं' वाले बयान पर रांका की दो टूक- हां हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं

नई दिल्ली, 04 सितंबर (वेब वार्ता)। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर और प्रवक्ता जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के शुरूआती समय में लगातार कहते रहे कि यहां राजनीतिक दलों की कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर धीरे-धीरे विपक्ष के कई बड़े चेहरे दिखाई दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद सीजेपी वाले खुदको एक प्रेशर ग्रुप की तरह पेश करने लगे।

लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकाक्षाओं की बहस तब तेज हो गई, जब 26 दिन भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक ने कहा- कि ये संत नहीं हैं, इनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। वांगचुक के इस बयान पर उखढ के आशुतोष रांका ने खुलकर बयानबाजी की है। रांका ने वांगचुक के बयान पर दो टूक शब्दों में कहा- ह्यहां, हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। इसके बाद CJP का असली मकसद भी बताया।

सोनम वांगचुक के बयान पर रांका की दो टूक

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान सोनम वांगचुक के बयान का जिक्र करते हुए आशुतोष रांका से पूछा गया- क्या उखढ के नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और क्या वह वांगचुक की बात से सहमत हैं? इसके जवाब में रांका ने कहा कि उन्होंने सोनम वांगचुक का पॉडकास्ट सुना है और उनसे इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई है। उनके मुताबिक, वांगचुक के कई बयान संदर्भ से हटाकर पेश किए जा रहे हैं।

रांका ने कहा कि वांगचुक ने सीजेपी के आंदोलन और उसके नेताओं की काफी तारीफ भी की थी। उन्होंने दावा किया कि वांगचुक ने कहा था कि उखढ के लोग देश के मौजूदा नेताओं से बेहतर हैं और आंदोलन के दौरान उनकी नीयत साफ और वास्तविक थी।

स्वरा भास्कर के खिलाफ दिल्ली के साइबर थाने में शिकायत

एससी की वकील बोलीं- अब माफी का वक्त गुजर चुका

नई दिल्ली, 04 सितंबर (वेब वार्ता)। फिल्म अभिनेत्र स्वरा भास्कर ने हाल ही में दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म 'पद्मावत' के एक सीन का जिक्र करते हुए 'जौहर' प्रथा पर आपत्ति जताई थी और इसे करने वाली महिलाओं को कायर बताया था। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई देते हुए इस विवाद को अनुवाद की गलती की उपज बताया था, लेकिन तब तक पूरे देश में उनके बयान पर गुस्सा भड़क चुका था। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक महिला वकील ने दिल्ली के एक थाने में शिकायत दी है और स्वरा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है।

साकेत साइबर पुलिस के एसएचओ को दी अपनी शिकायत में अमिता सचदेव नाम की इस महिला वकील ने स्वरा भास्कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की और कहा कि स्वरा ने 31 अगस्त को रानी पद्मावती और चित्तौड़ की हिंदू महिलाओं के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी की थी, जो कि उनके बलिदान का जानबूझकर अपमान करने और धार्मिक व सामुदायिक भावनाओं को आहत करने के समान है।

वकील बोलीं- स्वरा ने सबकुछ पता होने के बाद यह किया

पुलिस को दी अपनी शिकायत में महिला वकील ने कहा, 'मैं अमिता सचदेवा, एक प्रैक्टिसिंग वकील और सनातन धर्म की अनुयाई हूं और सुश्री स्वरा भास्कर के खिलाफ यह शिकायत दर्ज करा रही हूं। यह शिकायत 31 अगस्त के आसपास उनके द्वारा रानी पद्मावती और चित्तौड़ की उन हिंदू महिलाओं के बारे में की गई कुछ सार्वजनिक टिप्पणियों के संबंध में है, जिन्होंने जौहर किया था।' अमिता ने बताया कि स्वरा ने सबकुछ जानते-बुझते ऐसा किया और इसे उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ की अज्ञानता नहीं माना जा सकता।

दिल्ली के यमुना विहार में चार दिन से पानी का संकट, फटी पाइपलाइन से लोग बेहाल

नई दिल्ली, 04 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली के यमुना विहार क्षेत्र में पिछले चार दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड की पुरानी पाइपलाइन फटने से क्षेत्र में पानी की किल्लत है। गर्मी के बीच पानी नहीं मिलने से लोगों का बुरा हाल है और उन्हें रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे इलाकों से पानी लाना पड़ रहा है।

यमुना विहार बी ब्लाक क्षेत्र में पुरानी पाइपलाइन पिछले कुछ समय से जर्जर हालत में थी। यह आठ फीट गहरी व मुख्य पानी की लाइन है। इसे ठीक करने पर जल बोर्ड के पसीने छूट रहे हैं। जल बोर्ड नई लाइन डाल रहा है। चार दिन बीत जाने के बावजूद समस्या का स्थाई समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। कई परिवारों को पीने के पानी के साथ-साथ खाना बनाने, कपड़े धोने और अन्य घरेलू कामों के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

स्थानीय निवासियों ने जल बोर्ड से मांग की है कि पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत कराकर पानी की आपूर्ति बहाल की जाए। साथ ही, पुरानी और जर्जर पाइपलाइन को बदलने की भी मांग की गई है, ताकि बार-बार होने वाली इस तरह की समस्या से लोगों को राहत मिल सके।

चार दिन से पानी की एक बूंद नहीं आई है। पीने का पानी बाजार से खरीदना पड़ रहा है। पानी न होने की वजह से घर में बर्तन व कपड़े नहीं धूल रहे हैं।

आरएस धामा, अध्यक्ष आरडब्ल्यूए

चार दिन से पानी न होने से क्षेत्र में हाहाकार है। पानी न होने से लोग इस गर्मी में नहा भी नहीं पा रहे हैं। बाजार से पीने के पानी की बोतलें खरीदनी पड़ रही हैं।

महिपाल मावी, स्थानीय निवासी

पुरानी लाइन की मरम्मत होना आसान नहीं था। उसकी जगह नई लाइन डाली जा रही है। शुक्रवार से क्षत्र में पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा।

अजय महावर, विधायक घोंडा

शिक्षा समिति के चुनाव में योगेश वर्मा अध्यक्ष और अमित खड़खड़ी उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)

दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश वर्मा एडवोकेट को अध्यक्ष और अमित खड़खड़ी को उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। आम आदमी पार्टी की ओर से दोनों पदों के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया था।

निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद शिक्षा समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेश वर्मा एडवोकेट ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर दोबारा विश्वास जताया है, जिसके लिए वह नेतृत्व के आभारी हैं।

योगेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के करीब 1500 प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और विद्यालयों के शैक्षणिक एवं भौतिक स्तर में सुधार के लिए भी कार्य किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में कई नए और महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे, जिससे निगम विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर सुविधाएं और समान अवसर उपलब्ध कराना है। योगेश वर्मा ने कहा कि निगम के स्कूलों में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा उनकी जिम्मेदारी है और उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने अपने निर्विरोध निर्वाचन पर पार्टी कार्यकताओं, सहयोगियों, शिक्षा समिति के सदस्यों और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। वहीं, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अमित खड़खड़ी ने भी पार्टी नेतृत्व एवं सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षा समिति के अध्यक्ष के साथ मिलकर पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करने का विश्वास दिलाया।

पीएमओ का अधिकारी बनकर एम्स में मरीजों को करा रहा था भर्ती, सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर

नई दिल्ली, 04 सितंबर (वेब वार्ता)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का अधिकारी बताकर लोगों को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) में भर्ती कराया। सीबीआई ने धोखाधड़ी, झूठे सबूत देने और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला 31 अगस्त को दर्ज किया था। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक, मई 2026 में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के असिस्टेंट डायरेक्टर से रवि कांत शर्मा के खिलाफ एक लिखित शिकायत मिली थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसने पीएमओ अधिकारी बनकर खुद को पेश किया और पीएमओ के नाम का गलत इस्तेमाल किया। शिकायती पत्र में कहा गया है कि 26 फरवरी 2026 को रवि कांत शर्मा ने व्हाट्सएप के जरिए एम्स, नई दिल्ली के प्रोटोकॉल ऑफिसर से संपर्क किया। खुद को प्रधानमंत्री का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) बताया। साथ ही, एम्स अधिकारियों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उन्हें अपना ईमेल एड्रेस और शिकायतें और दूसरी संबंधित सेवाओं के लिए पीएमओ पोर्टल बताया।

आआपा पार्षदों ने महापौर कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन

चुनाव रद्द कर 35 सदस्यीय समिति बनाने की मांग

नई दिल्ली, 04 सितंबर (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आआपा) के निगम पार्षदों ने गुरुवार को अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण समिति का चुनाव कथित तौर पर निर्धारित समय से पहले कराए जाने के विरोध में सिविक सेंटर स्थित महापौर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आप पार्षदों ने चुनाव को रद्द कर समिति का पुनर्गठन करने की मांग की।

दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि समिति का चुनाव अपराह्न तीन बजे निर्धारित था, लेकिन इसे करीब दस मिनट पहले ही करा दिया गया। उन्होंने कहा कि समिति में सदस्यों की संख्या 35 से घटाकर 21 किए जाने को लेकर आप की ओर से पहले ही निगम को पत्र देकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी।

नारंग ने कहा कि आआपा की मांग है कि चुनाव को निरस्त कर समिति में सदस्यों की संख्या पूर्ववत 35 की जाए और इसके बाद नियमानुसार चुनाव कराया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विरोध दर्ज कराने पहुंचे पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आआपा की एमसीडी सह-प्रभारी प्रीति डोगरा ने कहा कि समिति में सदस्यों की संख्या कम किए जाने से दलित पार्षदों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि आप के पास दलित पार्षदों की संख्या अधिक होने के कारण पार्टी को समिति में बहुमत मिलने की संभावना थी। उन्होंने समिति को भंग कर 35 सदस्यों के साथ दोबारा गठित करने की मांग की।

निगम पार्षद सारिका चौधरी ने कहा कि एससी-एसटी कल्याण समिति में दलित पार्षद अपने क्षेत्रों से जुड़े सामाजिक एवं जनहित के मुद्दे उठाते हैं। उन्होंने समिति के गठन और चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे दोबारा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि मांग नहीं मानी गई तो पार्टी न्यायालय का रुख करेगी। निगम पार्षद मोहिनी जिनवाल ने भी चुनाव के समय को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आप पार्षदों की मांग है कि चुनाव रद्द कर 35 सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी दलित पार्षदों के प्रतिनिधित्व से जुड़े इस मुद्दे को आगे भी उठाएगी। प्रदर्शन के दौरान आआपा पार्षदों ने महापौर कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और समिति के चुनाव की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की मांग की।

पात्र व्यक्ति 30 सितंबर तक फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं नाम

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाने वाले पात्र मतदाता अब भी अपना नाम सूची में शामिल करा सकते हैं।

वे 30 सितंबर तक चल दावे और आपत्तियों के चरण में निर्धारित घोषणा पत्र और जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भर सकते हैं। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने ड्राफ्ट मतदाता सूची और अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट (एएसडीडी) सूची को लेकर प्रिंट और सोशल मीडिया में प्रकाशित खबरों में उठाए सवालों पर विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की गई थी।

कार्यालय के अनुसार, 30 जून से 17 अगस्त तक बीएलओ ने घर-घर जाकर पहले से छपे हुए गणना प्रपत्र वितरित किए और मतदाताओं का सत्यापन किया। इस दौरान जो मतदाता अपने पंजीकृत पते पर नहीं मिले या वहां से स्थानांतरित पाए गए, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एएसडीडी श्रेणी में रखा गया। बीएलओ ने घर-घर सत्यापन शुरू करने से पहले बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को इसकी जानकारी दी थी और उनके साथ समय-समय पर बैठकें भी की थीं।

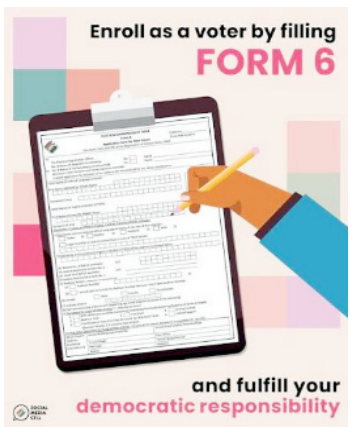

कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता को केवल अनुमान के आधार पर स्थानांतरित नहीं माना गया है। घर-घर सत्यापन के दौरान इसकी पुष्टि होने के बाद ही उसे इस श्रेणी में रखा गया। बीएलओ से मिली जानकारी के आधार पर एएसडीडी मतदाताओं की सूची भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रारूप में ईसीआई-नेट के माध्यम से तैयार की गई और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र निर्धारित समय में नहीं मिल सके, उन्हें पांच श्रेणियों में रखा गया है। इनमें मृत्यु, अप्राप्य या अनुपस्थित, स्थाई रूप से स्थानांतरित, पहले से नामांकित और अन्य श्रेणी शामिल हैं। किसी मतदाता को किसी खास कारण से संबंधित श्रेणी में रखने की जानकारी के लिए बीएलओ की ओर से अपलोड की गई बैठकों की कार्यवृत्त देखी जा सकती है।

एएसडीडी सूची में शामिल मतदाताओं के पते उपलब्ध नहीं कराए जाने के आरोपों पर कार्यालय ने कहा कि राजनीतिक दलों की ओर से मतदान केंद्र स्तर पर नियुक्त बीएलए-2 को बीएलओ के साथ हुई बैठकों में संबंधित मतदाताओं के पते नोट करने के लिए कहा गया था। राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर अपने बीएलए को बीएलओ से संपर्क कर एएसडीडी सूची में शामिल मतदाताओं के पते लेने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था।

संक्षिप्त वार्ता

ठुकरा के मेरा प्यार सीजन-2 में हरदोई की चेतना शुक्ला का खास गेस्ट अपीयरेंस

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। मनोरंजन जगत से हरदोई के लिए एक सुखद खबर सामने आई है। जिले की प्रतिभाशाली चेतना शुक्ला चर्चित वेब सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार सीजन-2 में खास गेस्ट अपीयरेंस करती नजर आ रही हैं। जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही इस सीरीज में चेतना का किरदार कहानी में एक दिलचस्प मोड़ लेकर आता है। सीरीज में चेतना शुक्ला लीड एक्ट्रेस के लिए अपने लड़के का रिश्ता लेकर पहुंचती हैं। रिश्ते की बातचीत से जुड़ा उनका यह किरदार कहानी में पारिवारिक रिश्तों और भावनाओं का एक नया रंग जोड़ता है। सीमित समय के इस गेस्ट अपीयरेंस में भी उनकी मौजूदगी दर्शकों का ध्यान खींच रही है। ठुकरा के मेरा प्यार का दूसरा सीजन इन दिनों दर्शकों के बीच चर्चा में है। सीरीज में संचिता बसु और धवल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। इसी चर्चित ओटीटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर चेतना शुक्ला ने हरदोई की प्रतिभाओं की मौजूदगी मनोरंजन के बड़े मंच पर दर्ज कराई है।

जीआरपी पुलिस ने शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार

वेब वार्ता, कानपुर

पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी० द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल ओमनारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे अपराधी को गठित टीम द्वारा करीब सौ (100) से अधिक सीसीटीवी फुटेज व धरातलीय सूचना पर कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन रेलवे प्रयागराज साइड पार्सल यार्ड से कुडाघर के पास एक शातिर अभियुक्त अमजद उर्फ सोनू पुत्र हल्के अब्दुल हमीद निवासी सलाबाद सोरार थाना कोतवाली जालौन जिला जालौन आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर किया। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से एक मंगलसूत्र पीली धातु अभियोग से सम्बन्धित बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब तीन लाख रुपए से अधिक है। गिरफ्तार अभियुक्त के अपराधिक इतिहास एंव अन्य सहयोगी सदस्यो की जानकारी की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में ओम नारायण सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल, सिध्दनाथ पाटीदार प्रभारी पोस्ट आरपीएफ कानपुर सेन्ट्रल, एस आई शशिकान्त सरोज, मनोज कुमार थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल, हे0का0 शिव सिंह, वैश खान, सत्येन्द्र सिंह, राज कमल वर्मा, का० अश्वनी कुमार, धर्मेन्द्र कुमार व आनन्द कुमार थाना जीआरपी कानपुर सेन्ट्रल रहे।

मेरा तालाब, मेरी जिम्मेदारी अभियान के अन्तर्गत जनपद में चयनित तालाबों की साफ-सफाई एवं स्वच्छता

कुशीनगर 4 सितम्बर (ममता तिवारी)। कुशीनगर जिले में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कल सायंकाल जिला स्वच्छता समिति की मासिक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जनपद में स्वच्छता एवं ठोस कूड़ा प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने ह्लमेरा तालाब, मेरी जिम्मेदारीह्व अभियान के अन्तर्गत जनपद में चयनित तालाबों की साफ-सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तालाबों की नियमित साफ-सफाई कराते हुए उन्हें स्वच्छ एवं उपयोगी बनाए रखा जाए।कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कूड़ा उठान में लगी गाड़ियों के नियमित एवं प्रभावी संचालन को प्राथमिकता देने तथा निर्मित कूड़ा प्रबंधन केन्द्रों पर कार्मिक नामित कर एकत्रित कूड़े का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों एवं सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को निर्देशित किया कि अपने-अपने विकास खण्डों में निर्मित कूड़ा प्रबंधन केन्द्रों का नियमित संचालन सुनिश्चित कराएं। कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कूड़ा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए विकास खण्ड रामकोला की सराहना करते हुए जिलाधिकारी ने अन्य विकास खण्डों को भी रामकोला की कार्यप्रणाली से प्रेरणा लेकर अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी कूड़ा प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने घोषणा की कि 02 अक्टूबर को कूड़ा प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले विकास खण्ड को पुरस्कृत किया जाएगा।

दिल्ली में सवाल पूछने पर महिला पत्रकारों को हिरासत! लोकतंत्र में पुलिसिया दबंगई बर्दाश्त नहीं : डॉ. राजेश त्रिवेदी

उप्र श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने साकेत थानाध्यक्ष के निलंबन की मांग की, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

लखनऊ। लोकतंत्र में सत्ता से सवाल करना पत्रकार का अधिकार ही नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी है। ऐसे में दिल्ली में मुख्यमंत्री से सवाल पूछने वाली महिला पत्रकारों नफीसा खान और शाहीन खान को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने तथा उनके साथ कथित मारपीट के मामले ने पत्रकार समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है। उप्र श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने घटना को पत्रकारिता की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर हमला बताते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की है।

यूनियन के प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में दिल्ली की घटना को लेकर पदाधिकारियों ने तीखा आक्रोश व्यक्त किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजेश त्रिवेदी ने कहा कि पत्रकार का काम सत्ता से सवाल पूछना है, सत्ता की चापलूसी करना नहीं। सवाल पूछने वाले पत्रकारों को पुलिस की ताकत के बल पर डराने या दबाने का कोई भी प्रयास लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।

डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि यदि किसी पत्रकार को उसके सवालों के कारण हिरासत में लिया जाता है और उसके साथ कथित मारपीट की जाती है तो यह केवल एक पत्रकार के अधिकारों का मामला नहीं रह जाता, बल्कि सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की गरिमा से जुड़ जाता है।

उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा प्रथमदृष्टया दोषी पाए जाने वाले साकेत थानाध्यक्ष और संबंधित महिला पुलिस अधिकारी को तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी कानून लागू करने का अधिकार देती है, कानून से ऊपर होने का नहीं।

पत्रकारों को डराने की कोशिश का जवाब आंदोलन से

यूनियन के प्रांतीय महासचिव रमेश शंकर पाण्डेय ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पत्रकार समाज इस तरह की कार्रवाई को मूकदर्शक बनकर स्वीकार नहीं करेगा। पत्रकार जनता की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। यदि पत्रकारों को ही सवाल पूछने पर पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा तो आम नागरिक अपने सवाल किससे पूछेगा?

उन्होंने दिल्ली सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। पाण्डेय ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो उप्र श्रमजीवी पत्रकार यूनियन आंदोलन का रास्ता अपनाएगी और पत्रकारों के सम्मान एवं अधिकारों की लड़ाई सड़क तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता को दबाने की किसी भी कोशिश के सामने पत्रकार समाज झुकने वाला नहीं है।

उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। बैठक में प्रांतीय पदाधिकारी रीना दीक्षित, रवि कश्यप, भूपेंद्र मणि त्रिपाठी, शशिकांत पाण्डेय, रविंदर सिंह और चंद्रगुप्त श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। सभी ने घटना की एक स्वर में निंदा करते हुए दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग की। बैठक में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि पत्रकारों को सवाल पूछने से रोकना लोकतंत्र की आवाज को रोकने के समान है। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि पत्रकारों के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और पुलिस प्रशासन ने मामले में शीघ्र निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन की अगली रणनीति तय कर पत्रकार समाज को लामबंद किया जाएगा।

महिला पत्रकारों की सुरक्षा पर भी उठे सवाल

प्रांतीय पदाधिकारी लक्ष्मीकान्त पाठक ने कहा कि महिला पत्रकारों के साथ कथित मारपीट और पुलिसिया दुर्व्यवहार की घटना विशेष रूप से गंभीर है। उन्होंने कहा कि महिला पत्रकारों को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। पत्रकारों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता।

65 हजार रुपये के ऑनलाइन लेनदेन के आरोप में महिला आरक्षी निलंबित

आंकिक शाखा से जुड़ा मामला, पुलिस अधीक्षक ने विभागीय जांच के दिए आदेश

वेबवार्ता, हरदोई

पुलिस विभाग की आंकिक शाखा से जुड़े 65,010 रुपये के कथित रिश्वत लेनदेन के मामले में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने महिला आरक्षी मोहिनी रानी (पीएनओ 162519424) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

पुलिस के मुताबिक, आंकिक शाखा में कार्यरत रहे उर्दू अनुवादक शकील अहमद पर 31 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त हुए उपनिरीक्षक मोहन लाल से वेतन संशोधन के बाद होने वाली वसूली को रोकने का लालच देकर कथित रूप से रिश्वत मांगने का आरोप है।

सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक की ओर से उपलब्ध कराए गए चित्र प्रमाण और बैंक लेनदेन के विवरण के आधार पर 65,010 रुपये ऑनलाइन माध्यम से आंकिक शाखा में संबद्ध महिला आरक्षी मोहिनी रानी के फोनपे खाते पर प्राप्त होने का आरोप सामने आया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल निलंबन की कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग ने अधिकारी-कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरतने की हिदायत दी है।

साथ ही, जांच में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।

लंबित विवेचनाओं में लापरवाही पर एसआई अनेकपाल सिंह निलंबित

वेबवार्ता, हरदोई। थाना बेहटा गोकुल में तैनात उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस अनेकपाल सिंह को कार्य सरकार में रुचि न लेने और अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू की गई है।

पुलिस के अनुसार उपनिरीक्षक अनेकपाल सिंह द्वारा लंबित विवेचनाओं के निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही थी। इसके अलावा गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के संबंध में समय से आख्या माननीय न्यायालय को प्रेषित नहीं की गई। पुलिस विभाग ने इन कार्यों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही माना है।

पुलिस अधीक्षक ने जनपद के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति किसी भी प्रकार की उदासीनता या शिथिलता न बरतें। लापरवाही सामने आने पर संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ हरदोई पुलिस का विशेष अभियान, 44 गिरफ्तार

लक्ष्मीकान्त पाठक, हरदोई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ हरदोई पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 3 सितंबर की रात चलाए गए इस अभियान में कोतवाली शहर, कोतवाली देहात और थाना सुरसा क्षेत्र में सघन चेकिंग एवं निगरानी की गई। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन कर रहे कुल 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं अनुशासित बनाए रखने तथा आमजन को भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में छह पुलिस टीमों को अभियान में लगाया गया। पुलिस टीमों ने शराब की दुकानों के आसपास के अलावा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर शराब का सेवन करने वाले लोगों की जांच की।

जांच के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर आमजन को असुविधा पहुंचाने तथा सार्वजनिक शांति भंग करने वाले लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई। कोतवाली देहात, थाना सुरसा और कोतवाली शहर पुलिस ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लगातार निगरानी करते हुए शराब सेवन करने वालों को पकड़ा। पुलिस

के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी 44 लोगों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई।

सुरसा में सबसे अधिक 26 गिरफ्तार

अभियान के दौरान थाना सुरसा पुलिस ने सबसे अधिक 26 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें थाना सुरसा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के साथ ही हरदोई और पड़ोसी जनपद उन्नाव के कुछ निवासी भी शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड में गिरफ्तार लोगों में जितेंद्र, सोनपाल, हिमांशु, गजराज, रामप्रवेश, मेहलाल, सर्वेश, प्रदीप, राजू, राधेश्याम सक्सेना, अल्पेश कुमार, रामू, राकेश, छेदीलाल, पिंटू, राजकुमार, मनोज कुमार, मनोज, दिनेश, रोहित, जागेश्वर, शंकर, अभिनेश, अशोक और गुड्डू समेत 26 लोगों के नाम दर्ज हैं।

कोतवाली देहात में 13 लोग पकड़े गए

कोतवाली देहात पुलिस ने भी व्यापक चेकिंग अभियान चलाते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में सुनील, आमीन, आदेश, कौशल, विनीत कुमार, सरताज, विपिन, कमलेश कुमार, रविन सिंह, रोहित, पप्पू, पंकज त्रिपाठी और राजकरू शामिल हैं। ये लोग कोतवाली देहात के अलावा जिले के अन्य थाना क्षेत्रों से भी संबंधित बताए गए हैं। वहीं कोतवाली शहर पुलिस ने अभियान के दौरान पांच लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें बिलग्राम थाना क्षेत्र के अमदापुर निवासी राजीव, मनीष और संजय तथा कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम आशा निवासी प्रदीप और चंदीपुरवा निवासी अनुराग शामिल हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वालों के विरुद्ध आगे भी प्रभावी चेकिंग और वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। हरदोई पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन न करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 51 शिक्षकों को किया गया सम्मानित

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई, 4 सितंबर। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव एवं हरदोई नगर पालिका अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी रामज्ञान गुप्ता ने जनपद के 51 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षकों को माला पहनाकर शाल, डायरी एवं पेन भेंट किए गए।

सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए रामज्ञान गुप्ता ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निमार्ता होता है और शिक्षा किसी भी देश के विकास की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार शिक्षा और विद्यालयों को बढ़ाने के बजाय धीरे-धीरे सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है, जो देश के भविष्य के लिए घातक है। निजी शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने और सरकारी शिक्षा तंत्र को कमजोर करने से शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा जैसी

महत्वपूर्ण व्यवस्था पूरी तरह निजी हाथों में चली गई तो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। देश में ह्यएक देश, एक शिक्षाह्व की व्यवस्था होनी चाहिए तथा शिक्षा पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देगी, तभी समाज में असमानता समाप्त होकर समानता स्थापित होगी।

अटेवा के प्रदेशीय सलाहकार ओम प्रकाश कनौजिया एवं सपा शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष जैनुल खान ने कहा कि निजीकरण देश के निम्न एवं मध्यम वर्ग के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, वह आने वाले समय में गंभीर परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। इस अवसर पर महेंद्र बर्मा, बृजलाल वर्मा, मोतीलाल यादव, ओमप्रकाश, महेश प्रसाद, जय प्रकाश नारायण, पतिराज गुप्ता, निशात अफरोज खान, राजाराम यादव, अशोक कुमार यादव, रामप्रताप सिंह, अजय कुमार, मो. इस्लाम, अविनाश कुमार, वीरेंद्र यादव, अरविन्द कुमार, सुनील कुमार मंडल, अरुण कुमार, आशीष कुमार, मंजू गुप्ता, सौरभ यादव, शुभम गुप्ता, शिवकुमार गुप्ता, विकास त्रिपाठी, आकाश गुप्ता, दुर्गेश यादव, धर्मेंद्र यादव, दीपू, शोभित यादव, सोनू गुप्ता, रामदत्त गुप्ता, चंद्र प्रकाश गुप्ता आदि मौजूद रहे।

महाराणा प्रताप महाविद्यालय में हर्षोल्लास से मना शिक्षक दिवस

डॉ. राधाकृष्णन के शिक्षा-दर्शन पर हुई संगोष्ठी

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई के बी.एड. विभाग में शिक्षक दिवस समारोह हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभागीय संगोष्ठी का आयोजन कर भारत के महान दार्शनिक, शिक्षाविद एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व, कृतित्व तथा उनके शिक्षा-दर्शन की समकालीन प्रासंगिकता पर विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर निखिलेश शरण ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित कर तथा डॉ. राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इसके बाद बी.एड. विभाग के शिक्षकों ने डॉ. राधाकृष्णन को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। बी.एड. विभाग के प्रभारी डॉ. प्रवेश कुमार ने शिक्षक दिवस के महत्व तथा डॉ. राधाकृष्णन के शिक्षा-दर्शन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। बी.एड. प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। गीतों एवं विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने शिक्षकों के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा व्यक्त की। डॉ. तारकेश्वर गुप्ता ने डॉ. राधाकृष्णन के जीवन एवं दर्शन पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉ. सुधीर कुमार ने प्रेरणादायी कविता का गायन कर विद्यार्थियों को उत्साहित किया।

गौशाला में संरक्षित प्रत्येक गोवंश के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान जरुरी : उपजिलाधिकारी

कुशीनगर 4 सितम्बर। कुशीनगर जिले मे आज दिनांक 04 सितम्बर 2026 को उप जिलाधिकारी पडरौना विवेक कुमार मिश्रा ने नगर पालिका पडरौना द्वारा संचालित बकुलहा स्थित कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान गौशाला में संरक्षित गोवंश के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।निरीक्षण के दौरान गौशाला में संरक्षित गोवंश के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा एवं स्वच्छ

पेयजल उपलब्ध पाया गया। गोवंश को हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गौशाला परिसर में हरे चारे की बुवाई कराने के निर्देश दिए गए। गौशाला परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई तथा कर्मचारी निर्धारित रोस्टर के अनुसार उपस्थित मिले।

उप जिलाधिकारी ने बताया कि गोवंश के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के साथ ही सभी संरक्षित गोवंश का समय से टीकाकरण कराने जरूरी है। उन्होंने कहा कि गौशाला में संरक्षित प्रत्येक गोवंश के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए तथा किसी भी प्रकार की बीमारी अथवा स्वास्थ्य संबंधी समस्या पाए जाने पर तत्काल आवश्यक उपचार सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने गौशाला में संरक्षित सभी गोवंश की शत-प्रतिशत जियो टैगिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए, ताकि गोवंश की प्रभावी निगरानी एवं अभिलेखों का नियमित सत्यापन किया जा सके। साथ ही गौशाला की निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही गोवंश को संरक्षित करने तथा क्षमता से अधिक पशुओं को रखने की स्थिति उत्पन्न न होने देने के निर्देश मौके पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए गए।

अयोध्या-काशी की तर्ज पर संवरेगा ब्रज: सीएम योगी

मथुरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या काशी के भव्य विकास के बाद अब ब्रजभूमि को भी जन-भावनाओं के अनुरूप विकसित किया जाएगा। डबल इंजन सरकार इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ब्रजभूमि के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यहां ऐसा भव्य परिसर तैयार किया जाएगा, जैसा अयोध्या और काशी में हुआ है। पिछली सरकारें श्रीकृष्ण जन्मभूमि आने से डरती थीं, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता होती थी। यह सरकार कृष्ण कन्हैया, प्रभु श्रीराम, बाबा विश्वनाथ और मां विंध्यवासिनी पर विश्वास करती है।

महत्वपूर्ण ख़बर

लापरवाही से गाड़ी चलाना पड़ेगा भारी ?

- नई दिल्ली। बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर अब सख्ती की तैयारी है। सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ग्रेडेड प्वाइंट सिस्टम लाने पर काम कर रही है। इसके तहत हर उल्लंघन पर लाइसेंस से प्वाइंट काटे जाएंगे। तय सीमा तक प्वाइंट कम होने पर लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकेगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को एसआईएएम के 66वें वार्षिक सम्मेलन में कहा, इसका मकसद लापरवाह चालकों पर नजर रखना। लोगों को जिम्मेदारी से वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रस्तावित व्यवस्था में हर ट्रैफिक उल्लंघन का रिकॉर्ड लाइसेंस से जुड़ा रहेगा। बार-बार नियम तोड़ने पर प्वाइंट लगातार कम होंगे। एक तय सीमा पार होने पर लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। गंभीर या लगातार उल्लंघन के मामलों में लाइसेंस रद्द भी हो सकता है।

40 किलो एक्सपायर्ड मिर्च, एक साथ वेज-नॉनवेज खाना...

- बेंगलुरु। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर के निदेर्शों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सहकारनगर स्थित चेयरमैन क्लब में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रसोई में एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ, मिसब्रांडेड सामान और वेज-नॉनवेज भोजन को एक साथ रखने जैसी गंभीर कमियां व अस्वच्छता पाई गई। विभाग ने स्वच्छता और सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद खाद्य पदार्थों को जब्त कर लिया गया और रसोई को तुरंत प्रभाव से बंद करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल, यह यह निरीक्षण 3 सितंबर को विभाग के खाद्य सुरक्षा विंग द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित लाइसेंसिंग और पंजीकरण नियमों के प्रावधानों के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. खादर के निदेर्शों के बाद किया गया था।

ईरान के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय संघ आए साथः तेल और वित्तीय नेटवर्क पर कसा शिकंजा, क्या बढ़ेगा आर्थिक संकट?

वॉशिंगटन। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि यूरोपीय संघ आधिकारिक तौर पर ईरान के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट में शामिल हो गया है।

यह अभियान ईरान को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से अलग करने और उसकी कमाई के उन रास्तों को रोकने पर केंद्रित है, जिनका इस्तेमाल अमेरिका के अनुसार परमाणु कार्यक्रम, हथियारों और आतंकवादी संगठनों के समर्थन के लिए किया जाता है। यूरोपीय संघ ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी जताई है, लेकिन साथ ही कूटनीतिक समाधान और तनाव कम करने पर भी जोर दिया है।

यूरोपीय संघ ने ईरान के खिलाफ क्या रुख अपनाया है?

बेसेंट ने कहा कि यूरोपीय संघ ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट में आधिकारिक रूप से शामिल होने की इच्छा जताई है और अमेरिका ने उसके शुरूआती कड़े रुख का स्वागत किया है। ईयू ने कहा कि ईरान को अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही उस पर क्षेत्र और यूरोप में अस्थिरता

फैलाने वाली गतिविधियां रोकने, यूक्रेन में रूस के युद्ध को सैन्य समर्थन बंद करने और अपने नागरिकों के खिलाफ हिंसा तथा दमन खत्म करने का दबाव बनाया गया है।

अमेरिका का ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट आखिर क्या है?

अमेरिका ने पिछले महीने यह अभियान शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ईरान को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क से काटना और उसकी आय के स्रोतों को सीमित करना है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े तेल नेटवर्क और प्रतिबंधों से बचने के तरीकों की पहचान करने की बात कही थी। इसके साथ डिजिटल संपत्ति, तकनीक और जहाजरानी से जुड़ी ईरान की गतिविधियों पर भी संभावित प्रतिबंधों के दायरे का विस्तार किया गया है। बेसेंट ने ईरान के सामने वैश्विक अलगाव या वैश्विक अर्थव्यवस्था में लौटने का रास्ता चुनने की बात कही थी।

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईयू ने क्या कहा?

यूरोपीय संघ ने कहा कि कूटनीतिक प्रयास जारी रहना जरूरी है, ताकि शांति समझौता हो सके और पश्चिम एशिया में स्थिरता लौटे। ईयू ने खास तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उसने कहा कि अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर वह आगे भी कदम उठा सकता है। ईयू ने ईरान पर पहले से लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों का भी उल्लेख किया।

ईयू ने कहा कि वह अमेरिका, जी7 और अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखेगा। हालांकि, उसके रुख में सैन्य या आर्थिक दबाव के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखने की बात भी साफ है। ईयू का कहना है कि ईरान को अपनी अस्थिरता पैदा करने वाली गतिविधियां रोककर सद्भावना के साथ शांति वार्ता में शामिल होना चाहिए। ऐसे में ईरान के खिलाफ पश्चिमी देशों का आर्थिक मोर्चा मजबूत होने के साथ कूटनीतिक प्रयास भी जारी रहने की संभावना है।

हो गया चमत्कार! नेपाल में तबाही के 9 दिन बाद सुरंग से जिंदा निकाले गए दो लोग

नेपाल। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बीच राहत की एक बड़ी खबर सामने आई है. 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के बाद सुरंग में फंसे दो हाइड्रोपावर कर्मचारियों को आखिरकार 9 दिन बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

लंबे समय तक मलबे और अंधेरे के बीच जिंदगी की जंग लड़ रहे इन दोनों कर्मचारियों के जिंदा बचने की खबर ने रेस्क्यू टीम और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी है.

रेस्क्यू किए गए कर्मचारियों की पहचान संजय साह और कविर महर्जन के रूप में हुई है. दोनों त्रिशूली-3 'अ' हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे और बाढ़ के बाद सुरंग के अंदर फंस गए थे. संजय साह नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी ठएअ में मैकेनिकल फोरमैन के पद पर कार्यरत हैं. वहीं कविर महर्जन त्रिशूली-3 'अ' हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में सुपरवाइजर के तौर पर काम करते हैं. बाढ़ के बाद सुरंग मलबे से पूरी तरह प्रभावित हो गई थी. ऐसे में दोनों कर्मचारियों तक पहुंचना बचाव दल के लिए बड़ी चुनौती बन गया था. लगातार प्रयासों और तकनीकी मदद के बाद आखिरकार रेस्क्यू टीम ने उन्हें बाहर निकालने में सफलता हासिल की.

पहले एक कर्मचारी निकला, फिर दूसरे की भी बची जान

न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक नेपाल के ऊर्जा मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ ने त्रिशूली-3अ की सुरंग से एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाले जाने की पुष्टि की. इसके कुछ ही समय बाद दूसरे कर्मचारी को भी बचा लिया गया. नेपाल के गृह मंत्री सूदन गुरुंग ने भी एक बयान में दूसरे व्यक्ति के बचाए जाने की जानकारी दी. नेपाल सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजा राम बस्नेत ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पहले कर्मचारी को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की पुष्टि की थी.

सुरंग के अंदर से सुनाई दीं और लोगों की आवाजें

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और उम्मीद जगी. स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार सुरंग के अंदर से अन्य लोगों की आवाजें भी सुनाई दीं. इससे बचाव दल का अभियान और तेज कर दिया गया है. इंजीनियर सुरंग के भीतर हवा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि यदि अन्य लोग अंदर फंसे हों तो उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे. सुरंगों में मौजूद लोगों तक पहुंचने के लिए मलबा हटाने और रास्ता बनाने का काम लगातार जारी है.

नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन ने हाइड्रोपावर परियोजनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचाया है. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक करीब 12 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स से लगभग 900 कर्मचारी लापता हैं. इनमें करीब 500 लोगों के सुरंगों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई गई है. ऐसे में संजय साह और कविर महर्जन का 9 दिन बाद जिंदा मिलना बाकी लापता लोगों के परिवारों के लिए भी उम्मीद की किरण बन गया है.

मराठा आरक्षण

जरांगे का सरकार को अल्टीमेटम, बोले- 11 सितंबर तक मांगे नहीं मानी तो मुंबई में करेंगे प्रदर्शन

मुंबई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे ने सरकार के साथ बातचीत के बाद भी आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने 11 सितंबर तक मांगें पूरी करने का समय दिया है और ऐसा नहीं होने पर 12 सितंबर को मुंबई जाकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जरांगे ने पात्र मराठों से कुनबी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने को भी कहा है। आखिर सरकार और जरांगे के बीच बात क्यों नहीं बनी और अब आंदोलन किस दिशा में जाएगा?

जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। एक सप्ताह से चल रहे इस आंदोलन के बीच गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों और विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने जरांगे से मुलाकात की, लेकिन बातचीत के बाद भी उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। जरांगे ने साफ कहा कि अगर 11 सितंबर तक मराठा समुदाय की सभी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह 12 सितंबर को मुंबई पहुंचकर आंदोलन करेंगे।

सरकार ने जरांगे को क्या भरोसा दिया?

सरकार की ओर से मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील और उदय सामंत, विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड और विधायक मकरंद पाटील जरांगे से मिलने पहुंचे। विखे पाटील ने उनकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए भूख हड़ताल खत्म या स्थगित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार मराठा समुदाय के मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के अनुसार करीब 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड खोजे जा चुके हैं और पात्र लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने की भी बात कही गई है।

जरांगे ने मराठों से क्या अपील की?

- सरकार के आश्वासन के बाद भी जरांगे पीछे नहीं हटे। उन्होंने शुक्रवार से पात्र मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन शुरू करने की अपील की।
- उन्होंने खास तौर पर हैदराबाद गजट में मिले रिकॉर्ड के आधार पर आवेदन करने को कहा।
- जरांगे के मुताबिक जिन परिवारों का संबंध पहचान किए गए कुनबी रिकॉर्ड से है, वे पारिवारिक संबंध, रक्त संबंध और वंश या कुल संबंध के आधार पर प्रमाणपत्र के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
- आवेदन में परेशानी आने पर उन्होंने संबंधित जिला कलेक्टर से तुरंत संपर्क करने की अपील की।

कुनबी प्रमाणपत्र की मांग क्यों महत्वपूर्ण है?

कुनबी एक कृषि आधारित समुदाय है और उसे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी में आरक्षण मिलता है। जरांगे की मांग है कि पात्र मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र दिया जाए, ताकि वे ओबीसी आरक्षण का लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि करीब 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड की पहचान हो चुकी है और पात्र परिवारों को कुनबी प्रमाणपत्र के साथ वैधता प्रमाणपत्र हासिल करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। सरकार की ओर से रिकॉर्ड मिलने और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया तेज करने का भरोसा दिया गया है, लेकिन जरांगे इसे अपनी सभी मांगों की स्वीकृति नहीं मान रहे हैं।

अजित पवार की मौत पर परिवार में ही रार

अजित पवार की मौत को लेकर उनके परिवार में मतभेद उभर रहे हैं। दरअसल सुप्रिया सुले ने अपने हालिया बयान में आरोप लगाया था कि अजित पवार की मौत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई और एनसीपी के नेता सत्ता के मजे ले रहे हैं। अब इस पर सुनेत्रा पवार ने पलटवार किया है।

मुम्बई। महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत को लेकर उनके ही परिवार में मतभेद उभरते दिखाई दे रहे हैं। राज्य की वर्तमान उपमुख्यमंत्री और दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के ताजा बयान से ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। दरअसल सुनेत्रा पवार ने विपक्षी नेताओं से अपने पति अजित पवार की मौत का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिवंगत नेता की मां, बच्चों और उनके दुख को कोई और नहीं समझ

सकता। ऐसा माना जा रहा है कि सुनेत्रा पवार ने परोक्ष रूप से सुप्रिया सुले पर तंज कसा है।

सुनेत्रा पवार ने क्या कहा?

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की इस साल 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती हवाईअड्डे के पास विमान हादसे में मौत हो गई थी। मौजूदा एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'सम्माननीय अजित दादा के निधन से महाराष्ट्र में जो शून्य पैदा हुआ है, वह बहुत बड़ा है। उनकी मां, उनके बच्चों और मेरे अलावा उस दर्द को कौन बेहतर समझ सकता है? इसलिए अजित दादा के साथ हुए हादसे का राजनीतिकरण न करें।'

प्रयास कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि परिवार और अन्य संबंधित लोग हादसे के बाद ठोस निर्णय चाहते थे और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा, 'हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पहले ही मिल चुके हैं। सभी इससे अवगत हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वादा किया है और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।'

वॉकर के सहारे रेलवे ट्रैक पार करता दिखा शख्स, लोगों ने बढ़ाया मदद का हाथ; वीडियो वायरल

अंबरनाथ। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म तक पहुंचना आम यात्रियों के लिए भले ही आसान हो, लेकिन दिव्यांग व्यक्ति के लिए यही रास्ता बड़ी चुनौती बन सकता है.

अंबरनाथ रेलवे स्टेशन का एक वीडियो इसी परेशानी को दिखाता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स वॉकर के सहारे रेलवे की पटरियों के बीच से गुजरता दिखाई देता है. वह धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, जबकि सामने वाले प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग उसकी ओर देखते रहते हैं. वीडियो में आगे कुछ लोग उसे प्लेटफॉर्म पर चढ़ने में मदद करते हुए भी नजर आते हैं.

वॉकर लेकर पटरियों के बीच चलता दिखा शख्स

सोशल मीडिया के इस वायरल वीडियो में शख्स अपने वॉकर को आगे रखकर पटरियों पर एक-एक कदम बढ़ाता नजर आता है. रेल की पटरियों के बीच बिछे पत्थरों और लोहे की पटरी पर चलना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं दिख रहा है . वह काफी मेहनत ओर सावधानी से आगे बढ़ रहा है

और सामने वाले प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंचने की पूरी लगन के साथ कोशिश करता है.

प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में लोगों ने की मदद

जैसे ही वो शख्स प्लेटफॉर्म के पास पहुंचता है, वहां मौजूद कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे भी आते हैं और वीडियो में लोग उसे पटरियों से प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ाने में भी मदद करते दिखाई देते हैं. और इसके बाद में वह वॉकर के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा नजर आता है और आसपास खड़े लोग भी उसके पास दिखाई देते हैं.

वीडियो पर यूजर्स ने किए तरह-तरह के कमेंट

वीडियो सामने आने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. एक सोशल मीडिया यूजर ने चिंता जताते हुए लिखा, अरे भाई, ट्रैक तुम पार कर रहे हो और मुझे डर लग रहा है. वहीं एक यूजर ने उस शख्स की मदद करने वाले व्यक्ति की तारीफ करते हुए कहा, भाई, वो बंदा उसे बचाने के लिए कूदा, उस भाई को दिल से सलाम है.

कई लोगों ने अंबरनाथ स्टेशन की सुविधाओं पर भी सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा, प्लेटफॉर्म 3 पर एस्केलेटर या लिफ्ट नहीं है क्या ? और ब्रिज भी काफी दूर है. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा की रेलवे इसके लिए जिम्मेदार है दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उस शख्स के हौसले की तारीफ की और एक यूजर ने सिर्फ मेहनत लिखकर इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

पिता ने बेटी को बेरहमी से मार डाला

शव देख फूट-फूटकर रोने लगी मां, बिलखते हुए बोलीं- कहां गई तू, वापस आ जा

आगरा। चंद्रवीर ने बेटी लविश्का (17) की प्रेम संबंध से नाराज होकर हत्या कर दी। उसने बांके से प्रहार कर गला दबाया। पिता ने थाने जाकर जानकारी दी। यह सवा महीने में तीसरी घटना है। पिता बेटी के प्रेम संबंध से नाराज होकर हैवान बन गया।

अपने ही हाथों से गला दबाकर बेटी को मार डाला। हत्या के बाद थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों को जानकारी दी तो वे भी सन्न रह गए। घर लौटी मां ने बेड पर बेटी का शव पड़ा देखा तो फूट-फूटकर रोने लगीं। कुछ ही देर में बेसुध होकर

गिर पड़ीं। पड़ोस की महिलाओं ने उन्हें संभाला। होश में आने पर रोते हुए एक ही बात बोल रही थीं...बेटी तू कहां चली गई, वापस आ जा। मैं बाहर क्यों गई जो बेटी की जान चली गई।

पंचगाई खेड़ा निवासी चंद्रवीर की बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान है। दो संतानों में बड़ा बेटा लवकुश पढ़ाई के बाद गुरुग्राम में चाचा के साथ नौकरी करता है। बेटी लविश्का (17) इंटरमीडिएट की छात्रा थी। वह दूसरी जाति के युवक से प्रेम करती थी। फोन पर बात करते देखकर पिता को शक हो गया था। उसे समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं मानी। मंगलवार को चंद्रवीर ने बेटी को डांट दिया तो वह घर से चली गई थी और देर रात वापस लौटी। तब तक पिता ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। बुधवार को वह बेटी को लेकर थाने बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। पुलिस ने बयान दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराया था। कोर्ट में बयान होने बाकी थे।

बृहस्पतिवार को लविश्का का भाई लवकुश गुरुग्राम चला गया था। दोपहर में मां रजनी भी घर से चली गईं। तभी चंद्रवीर ने बेड पर सो रही बेटी के सिर पर बांके से प्रहार किया। वह तड़पने लगी तो हाथों से गला दबा दिया। पड़ोसियों ने बताया कि आए दिन पिता-पुत्री के बीच झगड़ा होता था। पिता उसकी हत्या कर देगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था।

बेटी की हत्या के बाद पिता ने थाने आकर खुद ही जानकारी दी। उसे गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। - सय्यद अली अब्बास, डीसीपी सिटी

अल नीनो ने बढ़ाई चिंताः समुद्र के भीतर कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 8 डिग्री तक ज्यादा

नई दिल्ली। प्रशांत महासागर का असाधारण रूप से गर्म होता पानी दुनिया के मौसम के लिए बड़ी चेतावनी बन गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने कहा है कि अल नीनो सक्रिय हो चुका है और आने वाले महीनों में इसके बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचने की आशंका है।

इसके फरवरी 2027 तक बने रहने की संभावना करीब 100 फीसदी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह 2026 के अंत में चरम पर पहुंच सकता है। डब्ल्यूएमओ के अनुसार अल नीनो की तीव्रता मापने वाले नीनो 3.4 क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक पहुंच चुका है। जुलाई के अंत से अगस्त के मध्य तक साप्ताहिक तापमान सामान्य से 2.2 से 2.6 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। समुद्र के भीतर कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा ऊपर रहा। यह गर्मी अल नीनो के और मजबूत होने का संकेत दे रही है।

भारत में सिर्फ मानसून की कमी का खतरा नहीं

भारत के लिए इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल नीनो का असर पूरे देश में एक जैसा नहीं होगा। इसे केवल कमजोर मानसून के खतरे के रूप में देखना सही नहीं होगा। बारिश की मात्रा के साथ उसका वितरण और तीव्रता भी बदल सकती है। 100 से अधिक वर्षों के वर्षा आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि अल नीनो के दौरान दक्षिण-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी भारत जैसे अपेक्षाकृत सूखे क्षेत्रों में कुल बारिश और भारी बारिश की घटनाएं घट सकती हैं।

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और अधिक प्रयास जरूरी : राज्यपाल

वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम छत्तीसगढ़ का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज

रायपुर. राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उन्हें गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री सहज रूप से उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। तकनीक के माध्यम से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाने का वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम छत्तीसगढ़ का प्रयास सराहनीय और अनुकरणीय है।

वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम को उल्लेखनीय योगदान के लिए किया सम्मानित

राज्यपाल श्री डेका से लोक भवन में वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने टीम के सभी सदस्यों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। टीम की उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किए जाने पर उन्होंने सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम द्वारा दृष्टिबाधित एवं सामान्य विद्यार्थियों के लिए 11 हजार से अधिक ऑडियो बुक्स तैयार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस अभिनव अभियान की शुरुआत 5 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षिका सुश्री के. शारदा के नेतृत्व में हुई। सुश्री शारदा स्वयं अब तक 1,800 से अधिक ऑडियो बुक्स तैयार कर चुकी हैं। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के 30 शिक्षक- शिक्षिकाएं अपने नियमित शैक्षणिक दायित्वों के साथ इस कार्य में योगदान दे रहे हैं।

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने समान अवसर

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ऑडियो के माध्यम से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों को और व्यापक बनाने की जरूरत है, ताकि अधिक से अधिक दृष्टिबाधित विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें।

वर्ल्ड ऑडियो बुक चैनल को 8 लाख से अधिक बार देखा गया

वर्ल्ड ऑडियो बुक चैनल पर 107 से अधिक प्लेलिस्ट उपलब्ध हैं और इसे अब तक 8 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। टीम द्वारा विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम आधारित एवं उपयोगी अध्ययन सामग्री तैयार की जा रही है। इस अवसर पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की छत्तीसगढ़ हेड डॉ. सोनल राजेश शर्मा सहित वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम के सभी सदस्य उपस्थित थे।

ताजा खबर
संक्षिप्त

मुख्य सचिव ने विभागों में रिक्त पदों और भर्तियों की स्थिति की ली उच्च स्तरीय बैठक

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न प्रशासकीय विभागों में स्वीकृत, भरे और रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत विभागवार समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (व्यापमं) द्वारा आयोजित की जा रही भर्ती परीक्षाओं और भेजे गए इंडेंट (मांग पत्र) की प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही, विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग से मिली सहमति, पूर्व में विज्ञापित पदों की स्थिति तथा अब तक की गई नियुक्तियों का ब्योरा तलब किया गया। बैठक में वर्ष 2027 के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले संभावित पदों और सभी विभागों में अद्यतन (अपडेटेड) भर्ती नियमों की स्थिति पर भी गहनता से चर्चा हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य शासकीय विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं को गति देना, नियमों को अद्यतन करना और आने वाले वर्षों के लिए नियोजन की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना था। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न प्रमुख विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और छत्तीसगढ़ चयन मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बाल संरक्षण को लेकर प्रदेशभर में जागरूकता अभियान तेज

रायपुर. छत्तीसगढ़ में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, बाल अपराधों की रोकथाम और संकट की स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य बाल संरक्षण समिति के निर्देशन में प्रदेशभर में जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में रायपुर, बालोद और बेमेतरा की टीमों द्वारा स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों, किशोर-किशोरियों, शिक्षकों, अभिभावकों और आम नागरिकों को बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों एवं शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। रायपुर जिले में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, भाटागांव द्वारा स्काउट गाइड, बेमेतरा की टीम, बालिकाओं के समूह, धूम्रपान करते पाए गए बालकों तथा आने-जाने वाले यात्रियों को बाल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं आदर्श नियम 2016, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (च्व्ब्ै) 2012 एवं नियम 2020, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, दत्तक ग्रहण विनियम 2022 सहित मिशन वात्सल्य, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना, बाल सक्षम नीति और बाल संरक्षण नीति की जानकारी दी गई।

तीन नेताओं को मिला राज्यमंत्री का दर्जा, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने तीन प्रमुख नेताओं को राज्यमंत्री का दर्जा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया। इस फैसले के तहत छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष अजय शुक्ला और इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शरद अवस्थी को राज्यमंत्री की श्रेणी में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार तीन अलग-अलग निकायों में कार्यरत पदाधिकारियों को यह महत्वपूर्ण दर्जा प्रदान किया गया है। योग आयोग के प्रमुख के रूप में संजय अग्रवाल का मुख्य दायित्व प्रदेश भर में योग का प्रचार-प्रसार करना तथा स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। अजय शुक्ला को राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी के साथ राज्यमंत्री का दर्जा मिला है। यह बोर्ड विशेष रूप से वनांचल और आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों तथा औषधीय पौधों से जुड़ी गतिविधियों के संवर्धन के लिए कार्य करता है। तीसरे नेता शरद अवस्थी इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। इंद्रावती बेसिन के समग्र विकास तथा उससे जुड़े कार्यों के संचालन में इस प्राधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में नैक ग्रेडिंग, पीएचडी की गुणवत्ता, पाठ्यक्रमों और सामाजिक दायित्वों की समीक्षा

विद्यार्थियों का कल्याण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो विश्वविद्यालयों की सर्वोच्च प्राथमिकता : राज्यपाल

रायपुर. राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि विद्यार्थियों का कल्याण विश्वविद्यालयों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा के पवित्र मंदिर हैं, इसलिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। राज्यपाल रमेन डेका ने निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक लेकर विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को नैक (छ।।ब्) में बेहतर ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात संतुलित होना चाहिए तथा विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।

प्रत्येक विश्वविद्यालय में कम से कम 1000 विद्यार्थियों की संख्या सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने को कहा। श्री डेका ने कहा कि पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी तरह गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी होनी चाहिए। पीएच.डी. के लिए होने वाले पंजीयनों की विशेषज्ञों के माध्यम से रैंडम चेकिंग कराई जाएगी, ताकि शोध कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को केवल उपाधि प्रदान करने तक सीमित न रहकर ऐसे शोध को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसका समाज और देश के विकास में वास्तविक योगदान हो। राज्यपाल ने कहा कि कोई भी नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से पहले विश्वविद्यालय संबंधित क्षेत्र में सर्वेक्षण कर आवश्यकता और विद्यार्थियों की रुचि का आकलन करें। जिन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की संख्या नहीं है, उन्हें बंद करने पर विचार किया जाए। अनावश्यक रूप से पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाने के बजाय रोजगार एवं भविष्य की संभावनाओं वाले विषयों को प्राथमिकता दी जाए। श्री डेका ने एनवायरनमेंटल साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप इंटीग्रेटेड कोर्स को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया।

'विश्वविद्यालय गोद लिए गए गांवों में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका हो'

श्री डेका ने सभी निजी विश्वविद्यालयों को अपने आसपास के गांवों को गोद लेकर वहां शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नियमित कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने सामाजिक दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभाना चाहिए। गोद लिए गए गांवों में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों के साथ ब्रेस्ट कैंसर सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी विश्वविद्यालय सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को प्रत्येक विद्यार्थी तक योग पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों को योग के लिए इस प्रकार प्रेरित किया जाए कि यह उनकी दैनिक जीवनशैली और आदत का हिस्सा बन जाए। डेका ने छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ी भाषा से जुड़े विषयों पर शोध एवं अकादमिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि फार्मेसी सीधे मानव स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

इसलिए जिन विश्वविद्यालयों में फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित हैं, वहां विद्यार्थियों के बेहतर व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ टाई-अप किया जाए। उन्होंने फार्मेसी पाठ्यक्रम की गुणवत्ता के लिए नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री डेका ने विश्वविद्यालयों से नशा मुक्ति अभियान में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने तथा उन्हें नशे से दूर रखने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ओड़गी में विकास कार्यों की समीक्षा की

रायपुर. महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिला के ओड़गी के जनपद पंचायत सभाकक्ष में आयोजित विकासखंड स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक में शामिल होकर क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागवार योजनाओं और कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने तथा शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर योजनाओं एवं विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा आमजन से जुड़ी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए।

जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई योजनाओं के 36 कार्यों के लिए 146.43 करोड़ रूपए स्वीकृति

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा अपरीक्षित नवीन मद के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं के 36 कार्यों के लिए 146 करोड़ 43 लाख 95 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। स्वीकृत कार्यों में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के अंतर्गत खरला एनीकट योजना कार्य के लिए 4 करोड़ 69 लाख हजार 73 रूपए स्वीकृत किए है। प्रस्तावित कार्यों के होने पर क्षेत्र में 90 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा होगी। झिरियानाला स्टापडेम योजना के कार्य के लिए 3 करोड 87 लाख 17 हजार रूपए, योजना के कार्य पूर्ण होने पर 90 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। खटम्बर व्यपवर्तन योजना के नहर उन्नयन एवं सीसी चौनल निर्माण कार्य के लिए 4 करोड 93 लाख 08 हजार रूपए स्वीकृत किए है। योजना के कार्य होने पर 296 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। कोडांगी व्यपवर्तन योजना के नहरों का जीर्णोद्धार कार्य के लिए 3 करोड 38 लाख 72 हजार रूपए स्वीकृत किए है। योजना के कार्य पूर्ण होने पर 92 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। कौड़िया एनीकट योजना कार्य के लिए 4 करोड 50 लाख 99 हजाररूपए स्वीकृत किए है। योजना के कार्य पूर्ण होने पर 70 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। गुडरू व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर उन्नयन कार्य के लिए 4 करोड 99 लाख 15 हजार रूपए स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के कार्य पूर्ण होने पर 179 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

कोरिया जिले के सलबा जलाशय में बांध एवं नहर उन्नयन कार्य के लिए 2 करोड 19 लाख 97 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने पर 59 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। चम्पाझर जलाशय में नहर उन्नयन कार्य के लिए 1 करोड़ 95 लाख 99 हजार रूपए स्वीकृति प्रदान की गई है।

दावड़ा विवि में विधिक सहायता प्रकोष्ठ एवं प्रो बोनो क्लब विधि मितान का शुभारंभ

रायपुर। विधिक जागरूकता, सामाजिक सहभागिता एवं जमीनी स्तर तक न्याय पहुंचने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में श्री दावड़ा विश्वविद्यालय नवा रायपुर के स्कूल ऑफ लॉ में विधिक सहायता प्रकोष्ठ एवं इसके कार्यालय का उद्घाटन माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), रायपुर के सचिव श्री अविनाश दुबे द्वारा 02 सितंबर को किया।

इस अवसर पर प्रो बोनो क्लब विधि मितान का भी शुभारंभ किया गया। क्लब का उद्देश्य निःशुल्क विधिक सेवाओं, विधिक साक्षरता एवं जन-जागरूकता को बढ़ावा देना, समाज के गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों को विधिक सहायता से जोड़ना तथा विधि के विद्यार्थियों को व्यावहारिक विधिक सहायता कार्यों से जोड़ना है। कार्यक्रम के दौरान विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया। श्री अविनाश दुबे ने विद्यार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं न्याय तक समान पहुँच के महत्व से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने साइबर कानून, आईटी अधिनियम, रेलवे अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, बाल विवाह, घरेलू हिंसा एवं महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों तथा नालसा एवं सालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में सहजता से बताया। साथ ही नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के माध्यम से निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्राप्त करने की जानकारी भी दी गई।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय की माननीय महानिदेशक डॉ. चार्मी दावड़ा ने कहा कि विधिक सहायता प्रकोष्ठ एवं विधि मितान विद्यार्थियों को विधिक शिक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे तथा उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और न्याय की पहुँच को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करेंगे। विवि के सहायक प्राध्यापक एवं विधि अधिकारी यागवेन्द्र सिंह ने विधिक सहायता प्रकोष्ठ के पीठासीन अधिकारी के रुप में प्रकोष्ठ की विभिन्न गतिविधियों एवं भावी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी।

यह पहल विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय श्री चिन्मय दावड़ा के मार्गदर्शन एवं दूरदर्शी नेतृत्व में विधिक शिक्षा को सामाजिक उत्तरदायित्व एवं समुदाय-केंद्रित शिक्षा से जोड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कार्यक्रम में प्रो वाइस चांसलर डॉ. वरुण गंजीर, रजिस्ट्रार श्री विपिन श्रीवास्तव, डीन अकादमिक्स डॉ. नितिन जायसवाल, स्कूल ऑफ लॉ की प्रमुख डॉ. श्यामली नायडू, संकाय सदस्य श्री सूरज पांडे एवं सुश्री गुंजन दुग्गड़ सहित स्कूल ऑफ लॉ के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

डिजिटल युग में सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता एवं सतर्कता अत्यंत आवश्यक : रामविचार नेताम

रायपुर कृषि विवि में साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम

रायपुर. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में यहां छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा साइबर क्राइम के संबंध में जन जागरूकता उत्पन्न करने हेतु संचालित साइबर जागृति अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ शासन में कृषि विकास, किसान कल्याण तथा आदिम जाति मंत्री रामविचार नेताम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे तथा पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव शुक्ला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यशाला के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के प्रध्यापकों एवं विद्यार्थियों को साइबर क्राइम के विभिन्न पहलुओं, साइबर ठगी के विविध रूपों तथा इनसे सुरक्षा हेतु अपनाए जाने वाले एहतियातों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा राज्य में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु 15 अगस्त से 02 अक्टूबर 2026 तक साइबर जागृति अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों, बैंक खाता धारकों, आम नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों आदि को साइबर अपराध तथा उससे बचाव हेतु जागरूक किया जा रहा है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रामविचार नेताम ने कहा कि पूरे देश में साइबर अपराध एवं साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा प्रदेश के नागरिकों को साइबर अपराध में प्रति सचेत करने के लिए साइबर जागृति अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए छत्तीसगढ पुलिस की तारीफ की तथा अभियान की सफलता हेतु शुभकामनाएं दीं। श्री नेताम ने कहा कि डिजिटल युग में सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता एवं सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से साइबर अपराध, साइबर ठगी तथा इससे बचाव हेतु जागरूक एवं सतर्क रहने का आव्हान किया। पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव शुक्ला ने इस अवसर पर कहा कि देश में साइबर अपराध एवं ठगी के मामलों में पिछले चार सालों में 12 गुना वृद्धि हुई है जबकि इसी दौरान ठगी की राशि में 40 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार आज देश में प्रतिदिन 61 करोड़ रूपये की साइबर ठगी की जा रही है। उन्होंने कहा कि साइबर ठग, ठगी के नित नए तरीके ईजाद कर रहे हैं इसलिए लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा इसी बात को ध्यान में रखते हुए छः सप्ताह का साइबर जागृति अभियान संचालित किया जा रहा है।

कार्यशाला के दौरान रायपुर पुलिस के अधिकारियों द्वारा साइबर अपराध, साइबर ठगी तथा इससे बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम तथा आम नागरिकों को डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से साइबर जागृति अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक साइबर सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी पहुंचाना तथा नागरिकों को साइबर ठगी और ऑनलाइन अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करना है। वर्तमान डिजिटल युग में ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल भुगतान एवं अन्य इंटरनेट आधारित सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों के मामले भी सामने आ रहे हैं। साइबर अपराधी फर्जी कॉल, फिशिंग लिंक, ओटीपी फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी नौकरी एवं निवेश योजनाओं तथा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बनाने का प्रयास करते हैं।

41 वें चक्रधर समारोह में सजेगी कला की महफिल

स्थानीय से लेकर देश-प्रदेश के सुप्रसिद्ध कलाकार बिखरेंगे सुर और संस्कृति के रंग

रायपुर. महाराजा चक्रधर सिंह की कला-साधना और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समर्पित 41वें अंतर्राष्ट्रीय चक्रधर समारोह-2026 का भव्य आयोजन 14 से 23 सितम्बर तक रामलीला मैदान, रायगढ़ में होगा। स्थानीय प्रतिभाओं से लेकर देश-प्रदेश के सुप्रसिद्ध और नामचीन कलाकारों से सजे इस सांस्कृतिक महाकुंभ में दस दिनों तक सुर, ताल और नृत्य की अनूठी महफिल सजेगी। शास्त्रीय नृत्य की विविध विधाओं, छत्तीसगढ़ी लोककला, पंडवानी, लोकसंगीत, कबीर भजन, गजल और वाद्य प्रस्तुतियों के जरिए भारतीय कला एवं संस्कृति के अनेक रंग दर्शकों के सामने जीवंत होंगे। संस्कृति विभाग, पर्यटन मंडल एवं जनसहयोग से जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित समारोह में पद्मश्री सम्मानित कलाकारों के साथ इंडियन आइडल फेम कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधेंगे। प्रतिदिन शाम 6 बजे से शुरू होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं में हर दिन कला की एक नई विधा और नया रंग देखने को मिलेगा, जबकि 23 सितम्बर को पद्मश्री सम्मानित सुप्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति की सुरमयी प्रस्तुति के साथ समारोह का भव्य समापन होगा। समारोह का शुभारंभ 14 सितम्बर को श्री वेदमणि सिंह ठाकुर के शिष्यों द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति से होगा। इसके बाद पद्मश्री सम्मानित श्री अनुज शर्मा लोक कला एवं संगीत तथा पद्मश्री सम्मानित डॉ. उषा बारले पंडवानी की प्रस्तुति देंगी।

11 सितंबर को रिपोर्ट करता हूं

अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज पर बोले तिलक वर्मा

बंगलुरु। तिलक वर्मा की अगवाई वाली साउथ जोन की दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईस्ट जोन से टक्कर होगी। साउथ जोन और ईस्ट जोन के बीच 55 साल के बाद दलीप ट्रॉफी फाइनल खेला जाएगा, जो छह से 10 सितंबर तक चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा। साउथ जोन के कप्तान तिलक यह फाइनल नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनकी नजर दलीप ट्रॉफी फाइनल के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ पहला टी-20 मैच खेलने पर भी है। भारत को 13 से 17 सितंबर तक नई दिल्ली में अफगानिस्तान से तीन मैचों की टी-20 सीरीज में भिड़ना है।

भारतीय टी-20 टीम के उपकप्तान तिलक ने कहा, मैं दलीप ट्रॉफी फाइनल खेलना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच 13 सितंबर को है, इसलिए मैं फाइनल खेलने के लिए तैयार हूं। फाइनल और पहले टी-20 के बीच हमारे पास दो दिन का ब्रेक है। ऐसे में अगर मैं 11 तारीख को रिपोर्ट करता हूं, 12 तारीख को प्रैक्टिस करता हूं, तो फिर मैच में उतर सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है।

सबालेंका की यूएस ओपन में लगातार 16वीं जीत

न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के फ्लशिंग मीडोज में खेले जा रहे यूएस ओपन 2026 में दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने महिला सिंगल्स के दूसरे राउंड में रूस की क्वॉलिफायर पोलिना यात्चेंको को 6-1, 6-1 से हराकर तीसरे राउंड में जगह बना ली। सबालेंका ने यह मुकाबला सिर्फ 53 मिनट में जीता। महिलाओं में जेसिका पेगुला भी आगे बढ़ीं, जबकि मेंस सिंगल्स में डेनियल मेदवेदेव और बेन शेल्टन ने भी तीसरे दौर में जगह बनाई। अल्काराज ने आर्थर ऐश स्टेडियम में पुर्तगाल के जैमे फारिया को 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 से हराया।

पहला सेट गंवाने के बाद उन्होंने लगातार तीन सेट जीतकर 2 घंटे 39 मिनट में मुकाबला अपने नाम किया। गत विजेता सबालेंका शुरूआत से ही आक्रामक अंदाज में खेलीं। उन्होंने पहला सेट 6-1 से अपने नाम किया। दूसरे सेट में यात्चेंको ने एक गेम जीता, लेकिन इसके बाद सबालेंका ने लगातार तीन गेम जीतकर मैच खत्म कर दिया। सबालेंका की यूएस ओपन में यह लगातार 16वीं जीत है। वह फ्लशिंग मीडोज में लगातार तीसरा खिताब जीतने की कोशिश में हैं। तीसरे दौर में उनका सामना उज्बेकिस्तान की कामिला रखिमोवा से होगा।

पुरुष सिंगल्स में डेनियल मेदवेदेव ने अमरीका के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी सेबेस्टियन गोर्जनी को 6-1, 6-3, 7-5 से हराया। मैच के दौरान लुई आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में नेट पर दो छोटी चिड़ियां आ बैठीं। इस वजह से एक प्वाइंट दोबारा खेलना पड़ा और मेदवेदेव इस फैसले से नाराज भी दिखे।

पेगुला अगले दौर में

महिला सिंगल्स में अमरीकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने हमवतन सोफिया केनिन को 6-3, 6-1 से हराया। पेगुला ने यह मुकाबला 56 मिनट में जीता। 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन केनिन को पूरे मैच में वापसी का ज्यादा मौका नहीं मिला। पेगुला अगले दौर में कनाडा की लेयला फर्नांडीज से खेलेंगी। फर्नांडीज ने थाईलैंड की मननचाया सावांगकाएव को 6-4, 6-1 से हराया।

श्रीकांत चीन मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में

वर्ल्ड नंबर-9 विक्टर लाई को दी मात, तन्वी शर्मा हारकर बाहर

शेनझेन एरिना। चीन के शेनझेन एरिना में खेले जा रहे चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के अनुभवी खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। गुरुवार को दूसरे दौर में पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 श्रीकांत ने कनाडा के वर्ल्ड नंबर-9 विक्टर लाई को 21-18, 21-19 से हराकर उलटफेर किया। दूसरी ओर, महिला सिंगल्स में हाल ही में ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतने वाली तन्वी शर्मा जापान की वर्ल्ड नंबर-9 टोमोका मियाजाकी से 17-21, 21-18, 16-21 से हारकर बाहर हो गईं।

मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी भी दूसरे राउंड में हार गई। पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 श्रीकांत का क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेउक यू से सामना होगा। श्रीकांत इसी साल यूएस ओपन सुपर 300 के फाइनल में भी पहुंचे थे। वहीं, विक्टर लाई ने पिछले महीने नई दिल्ली में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वह इसी साल इंडोनेशिया में अपना पहला सुपर 1000 खिताब भी जीत चुके हैं।

एशिया कप में बैक टू बैक मैच जीतकर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए किया क्वालीफाई

हांगकांग। महिला एशिया कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गई है. गुरुवार की रात भारत ने हांगकांग के साथ खेले गए मुकाबले में 137 रनों से बड़ी जीत दर्ज की और अगले राउंड में पहुंच गई. बैक टू बैक 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई है. अब देखने वाली बात होगी कि बाकी की 3 टीमें कौन सी होती हैं. हांगकांग के साथ खेले गए मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, जिसमें 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 193 रन बोर्ड पर लगा दिए. भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने 124 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

स्मृति मंधाना बनीं महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने महिला एशिया कप 2026 में हांगकांग के खिलाफ खेले गए मुकाबले में इतिहास रच दिया है. स्मृति अपने ही देश की दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज को पीछे छोड़ते हुए महिला इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया.

जी हां, स्मृति मंधाना वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. तो आइए आपको उनके रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से बताते हैं.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने गुरुवार को हांगकांग के खिलाफ खेले गए मुकाबले में स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी की और 124 रनों की पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 7 छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 193.7 5 का रहा. इसी के साथ स्मृति महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गए हैं. वह सबसे तेजी से 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने सिर्फ 281 पारियों में यह मुकाम हासिल किया. वह खेल के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं.

इसी के साथ मंधाना ने मिताली राज के 10,868 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. शानदार बाएं हाथ की बल्लेबाज अब इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं; उनसे पीछे न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स (10,740 रन) और रिटायर हो चुकीं मिताली राज हैं.

धोनी आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बनेंगे, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ का दावा, विकेटकीपर के तौर पर रहना चाहते हैं

नई दिल्ली। एमएस धोनी आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं खेलना चाहते हैं। वह फुलटाइम विकेटकीपर के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होना चाहते हैं।

यह दावा चेन्नई सुपर किंग्स में उनके टीममेट रहे पूर्व बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने किया। उन्होंने यूट्यूब वीडियो में दावा किया कि धोनी ने खुद उनसे यह बात कही कि वह पूरे 20 ओवर मैदान पर रहना चाहते हैं। धोनी 2026 के सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला था। 2027 सीजन में भी वह खेलेंगे या नहीं, इस पर धोनी या टीम की ओर से ऑफिशियल बयान अब तक नहीं आया है। बद्रीनाथ ने यह भी कहा कि धोनी का शरीर लंबे समय तक यह काम नहीं संभाल सकता।

सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग भी इस बारे में कह चुके हैं। बद्रीनाथ ने कहा, धोनी 16वें ओवर के बाद ही बल्लेबाजी करने वाले हैं और विकेटकीपिंग भी करेंगे। जब

उनकी भागीदारी इतनी कम है, तो वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलना ही सही होगा। धोनी पिछले कुछ सीजन से फिटनेस से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। धोनी ने सीएसके को पांच (2010, 2011, 2018, 2021 और 2023) आईपीएल खिताब जिताए हैं। उन्होंने 2024 सीजन से पहले कप्तानी छोड़ दी थी। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वालों में महेंद्र सिंह धोनी तीसरे नंबर पर हैं। वह अब तक 278 मैच खेल चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार खिताब जिताया है।

आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले इकलौते कप्तान

धोनी आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा 235 मैचों में कप्तानी की है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं। उन्होंने 158 मैचों में कप्तानी की है। धोनी ने अपनी कप्तानी में सीएसके को 2023 में आखिरी बार चैंपियन बनाया था। धोनी अपनी कप्तानी में टीम को 136 मैचों में जीत दिला चुके हैं, जबकि 97 में टीम को हार मिली।

कारोबार

नोएल टाटा को बड़ी राहत: 37 साल पुराने सौदे में क्लीन चिट

833 शेयरों के ट्रांसफर पर क्यों उठे थे सवाल?

मुंबई। नोएल टाटा को 37 साल पुराने 833 शेयरों के ट्रांसफर मामले में बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर ने शिकायत खारिज कर दी और सौदे को उस समय के नियमों के मुताबिक सही माना। आखिर इस पुराने सौदे पर सवाल क्यों उठे थे और अब जांच की जरूरत क्यों नहीं मानी गई?

टाटा संस और टाटा ट्रस्ट में चल रही खींचतान के बीच नोएल टाटा को कानूनी राहत मिली है। महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर ने उन्हें 1989 के शेयर ट्रांसफर मामले में क्लीन चिट दी है। मामला नवाजबाई रतन टाटा ट्रस्ट (एनआरटीटी) द्वारा 833 शेयरों के ट्रांसफर से जुड़ा था। चैरिटी कमिश्नर ने ट्रस्टी विजय सिंह की शिकायत खारिज कर दी। सिंह ने सौदे की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। कमिश्नर ने आदेश में कहा कि शेयर ट्रांसफर तत्कालीन कानूनी प्रावधानों के तहत किया गया था। इसलिए इसमें आगे की जांच की जरूरत नहीं है। क्लीन चिट मिलने पर ट्रस्ट ने आरोपों को निराधार बताया। ट्रस्ट ने कहा, यह संस्थान की साख को नुकसान पहुंचाने का अभियान था।

विजय का आचरण अशोभनीय : कमिश्नर ने विजय के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए। सिंह 8 जून को बोर्ड बैठक में शामिल हुए थे। इसमें ट्रस्ट का पक्ष रखने का प्रस्ताव पारित हुआ, पर 10 जून को उन्होंने गुपचुप अपनी अलग शिकायत दर्ज करा दी। चैरिटी कमिश्नर ने उनके इस आचरण को एनआरटीटी के ट्रस्टी के रूप में अशोभनीय बताया।

इन आधार पर मिली क्लीन चिट

कमिश्नर ने दस्तावेज की पड़ताल कर 37 साल पुराना सौदा नियमों के तहत पाया। शेयरों की बिक्री उस समय के वैधानिक कर नियमों की बाध्यताओं के तहत जरूरी थी। नवल नोएल टाटा ने 1 जनवरी 1988 को ट्रस्टी पद से इस्तीफा दिया था। नानी ए. पालकीवाला ने इस्तीफे के एक साल बाद शेयर खरीदने पर रोक न होने की बात कही थी। शेयरों का मूल्यांकन वेल्थ टैक्स कमिश्नर की सहमति से हुआ और एनआरटीटी को शुद्ध वित्तीय लाभ मिला।

अल नीनो और सूखे का असर

इंडोनेशिया में घटेगा पाम तेल उत्पादन; क्या भारत में बढ़ेंगी कीमतें?

नई दिल्ली। इंडोनेशिया में अल नीनो और सूखे से पाम तेल का उत्पादन 50 लाख टन तक घटने का अनुमान है। ऊपर से बी50 नीति से घरेलू खपत बढ़ने वाली है। ऐसे में वैश्विक बाजार में आपूर्ति घट सकती है और भारत की चिंता बढ़ सकती है। क्या इसका असर आपकी रसोई के तेल के दाम पर भी पड़ेगा?

इंडोनेशियाई पाम ऑयल एसोसिएशन (गैपकी) ने चेतावनी दी है कि अल-नीनो और सूखे के चलते इंडोनेशिया में क्रूड पाम तेल (सीपीओ) उत्पादन में 50 लाख टन तक की भारी गिरावट आ सकती है। इसका असर अगले साल की शुरूआत से ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर साफ दिखने लगेगा। इंडोनेशिया में एक तरफ मौसम की मार से फसल पर खतरा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के नेतृत्व में सरकार डीजल आयात घटाने के लिए पाम-आधारित बायोडीजल की ब्लेंडिंग 40 फीसदी (बी40) से बढ़ाकर 50 फीसदी (बी50) करने जा रही है।

गैपकी के चेयरमैन एडी माटोनो के अनुसार, देश में कुल 5.3 करोड़ टन उत्पादन का अनुमान है लेकिन बी50 नीति लागू होने से अकेले बायोडीजल के लिए 1.63 से 1.70 करोड़ टन पाम तेल की खपत घरेलू स्तर पर ही हो जाएगी। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाने वाले निर्यात मात्रा में भारी कटौती होगी यानी वैश्विक बाजार के लिए पाम तेल की उपलब्धता तेजी से घटेगी।

अन्य तेलों पर भी दिखेगा असर : पाम तेल दुनिया का सबसे सस्ता खाद्य तेल है। जब पाम तेल महंगा होता है, तो मांग तुरंत सोयाबीन और घरेलू सरसों तेल की तरफ शिफ्ट होती है। नतीजतन, सरसों और रिफाइंड तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत अपनी खाद्य तेल जरूरतों का लगभग 55 से 60 फीसदी हिस्सा आयात करता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा (सालाना करीब 90-100 लाख टन) पाम तेल का होता है। भारत अपनी पाम तेल की जरूरतें मुख्य रूप से दो ही देशों, इंडोनेशिया और मलेशिया, से पूरी करता है। यदि इंडोनेशिया में निर्यात घटता है और साथ ही दूसरे बड़े उत्पादक मलेशिया में भी अल-नीनो के कारण फसल कमजोर होती है, तो भारत पर इसका असर गंभीर होगा।

सरकार ने कहा कि देश में खाद्य तेल पर चिंता की कोई बात नहीं है। बाजार में 14-15 लाख टन खाद्य तेल का स्टॉक है, जो करीब डेढ़ महीने की घरेलू मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है। सितंबर से सोयाबीन और मूंगफली की नई फसल की आवक शुरू होने की उम्मीद है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2025 से अब तक देश में 120 लाख टन खाद्य तेल का आयात हो चुका है। पिछले साल इसी अवधि में करीब 116 लाख टन खाद्य तेल का आयात हुआ था।

व्यापार जगत की सुर्खियां: डीलरों को अब ई-रुपये में कमीशन का भुगतान; भारत-न्यूजीलैंड एफटीए अगले माह होगा लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन डीलरों को बड़ी राहत देगी। अब उन्हें करीब 2,900 करोड़ रुपये के कमीशन का भुगतान ई-रुपये से तुरंत मिलेगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसका खाका तैयार कर वित्त मंत्रालय को सौंपा है। देश में लगभग 5.43 लाख उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। वर्तमान में डीलरों को कमीशन भुगतान में महीनों की देरी और जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित प्रणाली शुरू हो रही है। एनएफएसए के तहत 78.85 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने लगभग 19,000 करोड़ रुपये का राशन वितरित होता है। इसमें सालाना करीब 2,900 करोड़ रुपये का कमीशन डीलरों के हिस्से आता है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अगले महीने से लागू होने की उम्मीद है। इस समझौते पर दोनों देशों ने 27 अप्रैल को हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य वस्तुओं व सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है। समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारतीय निर्यातकों को 100% उत्पादों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। इससे सिरेमिक, कालीन, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे प्रमुख भारतीय उत्पादों पर लगने वाला 10% तक का शुल्क समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। बातचीत अंतिम चरण में है।

वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कर्नाटक में दुर्लभ खनिज (आरईई) ब्लॉक के लिए खनन पट्टा हासिल किया है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, कर्नाटक सरकार ने चामराजनगर जिले में 314.21 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले दुर्लभ खनिज और इट्रियम ब्लॉक का खनन पट्टा कंपनी को देने के मकसद से आशय पत्र (एलओआई) जारी किया है। आरईई आधुनिक तकनीक के लिए बहुत महत्वपूर्ण खनिज हैं। इनका इस्तेमाल स्मार्टफोन और ई वाहनों में होता है।

सियाम के नए अध्यक्ष बने शेनू अग्रवाल

वाहन कंपनियों के संगठन सियाम ने अशोक लेलैंड के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ शेनू अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए अपना नया अध्यक्ष चुना है। वह टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लि के एमडी शैलेश चंद्र का स्थान लेंगे। वहीं, टीवीएस मोटर के निदेशक केएन राधाकृष्णन को सियाम का उपाध्यक्ष चुना गया है।

महत्वपूर्ण ख़बर

बालाघाट में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और डिलीवरी व्यवस्था करें सुदृढ़

■ भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बालाघाट जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता और डिलीवरी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभागों के बीच समन्वित एवं परिणाम आधारित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बालाघाट की भौगोलिक एवं दुर्गम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की योजना और मानव संसाधन का निर्धारण वास्तविक आवश्यकता एवं क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुरूप किया जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री सुखवीर सिंह, सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती जी.वी. रश्मि, आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री धनराजू एस., मिशन संचालक एनएचएम डॉ. सलोनी सिडाना सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश के मलखंब खिलाड़ियों को मिली बड़ी सौगात

■ भोपाल। मध्यप्रदेश में मलखंब खेल और खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग के प्रयासों से बड़ी पहल की जा रही है। प्रदेश में मलखंब खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मलखंब एवं जिम्नास्टिक अकादमी विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। लगभग 20 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाली इस अकादमी में खेल अधोसंरचना, हॉस्टल, आधुनिक खेल उपकरण और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

भोपाल पुलिस का फिटनेस टेस्ट: 62% जवान कसौटी पर नहीं उतरे खरे

248 'युवा' पुलिसकर्मी 1 घंटे में भी नहीं दौड़ पाए 10 किमी

भोपाल। राजधानी में पुलिसबल को चुस्त-दुरुस्त और एक्टिव बनाए रखने के मकसद से शुरू की गई 'सैटरडे रनिंग ड्राइव' के पहले ही नतीजों ने वरिष्ठ अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस विभाग द्वारा कराए गए इस फिटनेस टेस्ट में शामिल हुए लगभग 62% पुलिसकर्मी तय मानकों को पूरा करने में असफल रहे।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 45 वर्ष से कम आयु वाले जिन युवा जवानों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, उनमें से भी करीब 62% जवान निर्धारित समय में दौड़ पूरी नहीं कर सके। राजधानी के सभी 12 एसीपी संभागों में आयोजित इस प्रक्रिया में कुल 560 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 349 जवान तय समय में लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहे।

45 वर्ष से कम उम्र (लक्ष्य: 60 मिनट में 10 किमी)

इस श्रेणी में शामिल 396 पुलिसकर्मियों में से केवल 148 जवान ही समय पर दौड़ पूरी कर पाए, जबकि 248 (62% से अधिक) असफल रहे। मिसरोद (70), निशातपुरा (49) और कोतवाली (21) संभाग के युवाओं में से एक भी जवान निर्धारित समय में दूरी तय नहीं कर सका। वहीं, शाहजहांनाबाद में 53 में से मात्र 4 जवान सफल हुए। सकारात्मक पहलू यह रहा कि जहांगीराबाद के सभी 26 और टीटी नगर के सभी 22 जवानों ने दौड़ सफलता से पूरी की।

45 से 55 वर्ष की उम्र (लक्ष्य: 45 मिनट में 5 किमी)

इस वर्ग में भाग लेने वाले 118 पुलिसकर्मियों में से 53 ही सफल रहे, जबकि 65 पिछड़ गए। कुल 55% असफल रहे।

55 वर्ष से अधिक उम्र (लक्ष्य: 25 मिनट में 3 किमी)

सीनियर श्रेणी के 46 कर्मचारियों में से महज 10 ही लक्ष्य तक पहुंच पाए।मिसरोद (14) और निशातपुरा (8) के सभी पुलिसकर्मी इस टेस्ट में असफल साबित हुए।

अभ्यास के लिए मिलेगा और समय

जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि कुछ थानों में जवानों ने दौड़ने के बजाय केवल स्ट्रेचिंग ही की, जबकि 55 से अधिक उम्र के कई जवानों ने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का हवाला देकर योग का विकल्प चुना।

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के अनुसार, विभाग के सर्कुलर के आधार पर ही जुलाई से फिटनेस स्टैंडर्ड लागू किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो पुलिसकर्मी अभी मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, उन्हें पर्याप्त अभ्यास का अवसर दिया जाएगा, लेकिन पुलिसबल की फिटनेस से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

शिक्षक दिवस पर प्रदेश सरकार 33 उत्कृष्ट शिक्षकों को करेगी राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित

भोपाल। प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह समारोह राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में होगा।

5 सितंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, जनजातीय कार्य लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह और खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता विभाग मंत्री श्री विश्वास सारंग विशेष अतिथि होंगे।

लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त श्री अभिषेक सिंह ने बताया कि कार्यक्रम सुबह 10.30 बजे से होगा। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा उन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, शैक्षणिक नवाचारों को बढ़ावा देने और विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण निर्मित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय पुरस्कार-2026 के लिए चयनित शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और 25,000 हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर अलंकृत किया जाएगा। समारोह में विगत वर्ष 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित दो शिक्षकों का विशेष सम्मान भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा मध्यप्रदेश से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2025 के लिए चयनित एवं राष्ट्रपति से सम्मानित 2 उत्कृष्ट शिक्षकों श्रीमती शीला पटले और श्री भेरूलाल औसारा को समारोह में शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र तथा सम्मान राशि प्रदान कर विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।

इन शिक्षकों का होगा सम्मान

सुश्री पूनम मिश्रा, श्री बिहारी लाल प्रजापति, श्री अरूण कुमार भादे, श्री बलराम अहिरवार, श्री मुकेश कुमार शर्मा, श्री अरूण कुमार मित्तल, श्री मुकेश कुमार प्रजापति, श्री मनीष तिवारी, श्री अजय कुमार मिश्रा, श्री मुकेश नागर, श्री राजेश महेश्वरी, श्री मोहित कुमार गर्ग, सुश्री पूजा पाण्डेय, श्री सतीश कुमार पाण्डेय, सुश्री श्वेता तिवारी, श्री शिवलाल दांगी, श्री धन्नालाल बिसेन, श्री रितेश कुमार पथाडे, श्री सुखनंदन साहू, श्री नरेन्द्र कुमार भारद्वाज, श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा, श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, श्री राकेश कुमार गुप्ता, सुश्री शिखा शर्मा, श्री महेन्द्र सिंह पवार, सुश्री ज्योति पाठक, श्री राकेश कुमार वर्मा, श्री सुरेश चंद्र सोनी, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, सुश्री रीना देवी कटरे, श्री हेमंत कुमार वैद्य, श्री राकेश कुमार द्विवेद्वी एवं सुश्री सीमा परमार शामिल हैं।

वरिष्ठ अधिकारी दूरस्थ जिलों का भ्रमण कर शिकायतों का निराकरण कराये

भोपाल। मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में मंत्रालय में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान एवं बालाघाट प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव श्री बर्णवाल ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान अंतर्गत दूरस्थ जिलों का भ्रमण कर शिकायतों का निराकरण कराने के निर्देश दिये। श्री बर्णवाल ने सी.एम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण के निर्देश देते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारी कुछ शिकायतकर्ताओं से स्वयं बात करें। विभागों में प्राप्त शिकायतों के कारणों को ढूंढकर उनका समाधान कराएँ। मुख्य सचिव ने सभी-अधिकारियों को भारत सरकार के पत्रों के जवाब अनिवार्यत: 15 दिन में देने के निर्देश भी दिए।

फिल्म हनुमान अंश के गायक श्री लोधी को करेगी राज्य सरकार प्रोत्साहित : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिलने मुख्यमंत्री निवास पहुंचे युवा बुंदेली गायक

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से गुरूवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) उदीयमान युवा बुंदेली गायक सागर निवासी श्री सुनील लोधी ने भेंट की। जन्म से ही दृष्टिबाधित श्री लोधी ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश के लिए बुंदेली में गीत गाया है, जो तेजी से लोकप्रिय हुआ है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री लोधी को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शाबासी देते हुए राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग देने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा श्रेष्ठ कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए अधिक से अधिक अवसर देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर श्री सुनील लोधी और उनके माता पिता का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित युवा गायक श्री लोधी को एक लाख रुपए की सम्मान निधि भी प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री लोधी की आंखों की रोशनी लाने के लिए भी आवश्यक सहयोग देने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चूंकि बाल्यकाल से गायन क्षेत्र में लोधी की अभिरूचि है, इस नाते उन्हें संगीत विद्यालय से औपचारिक संगीत पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए भी सहयोग दिया जाएगा। टैलेन्ट सर्च जैसे कार्यक्रम चलाकर ऐसे होनहार गायकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुलाकात के अवसर पर सुनील लोधी के पिता श्री महेन्द्र सिंह लोधी और माता श्रीमती भाग बाई के साथ ही संस्कृति सलाहकार श्री श्रीराम तिवारी, डिजिटल बुंदेली बौछार के श्री सचिन चौधरी और गायक श्री लोधी के मित्रगण उपस्थित थे।

गीत और भजन भी सुनाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को गायक श्री सुनील लोधी ने फिल्म हनुमान अंश के लोकप्रिय हुए गीत मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई को तंबूरा बजाते हुए सुनाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला भजन जन्म लए रघुराई, ब्रज में बज रही बधाई भी गाकर सुनाया।

देर रात जमकर बरसे बादल, मानसून सीजन में 526 मिमी बारिश; औसत से 18 प्रतिशत कम

इंदौर। इंदौर जिले में इस मॉनसून सीजन में अब तक 526 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है जो कि अब तक औसत से 18 प्रतिशत कम है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश कारण अब तक की औसत बारिश से एक प्रतिशत अधिक बारिश हुई है।

वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में अब तक औसत बारिश से 17 प्रतिशत कम पानी बरसा है। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इंदौर में शुक्रवार को दिनभर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। यह स्थिति अगले दो दिन बनी रहेगी।

इंदौर में पांच घंटे में हुई 17.8 मिलीमीटर बारिश

इंदौर शहर में ढाई बजे शुरू हुई वर्षा सुबह साढ़े आठ बजे तक जारी रही। इसके बाद कुछ देर के लिए बारिश थमी। इंदौर में पांच घंटे में 17.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं जिले के सांवेर तहसील में सबसे अधिक 22.9 मिलीमीटर बारिश देपालपुर में 4.8 मिलीमीटर बारिश, गौतमपुरा में 7.6 मिलीमीटर बारिश हातोद में दो और महू में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

मौसम अपडेट

निम्न दबाव का क्षेत्र, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र पर बना पर उसी क्षेत्र में बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 7.6 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण उत्तर प्रदेश और उससे लगे उत्तर मध्य प्रदेश से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है।

मानसून ट्रफ, माध्य समुद्र तल पर अब श्रीगंगानगर, रोहतक, फतेहगढ़, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और उसके आसपास के स्पष्ट कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र, डाल्टगंज, दीघा और वहां से पूर्व-दक्षिण-पूर्व की ओर पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक गुजर रहा है। ट्रफ, उत्तर-पूर्वी अरब सागर और उससे सटे सौराष्ट्र के चक्रवाती परिसंचरण से लेकर पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश व आसपास के स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र से जुड़े चक्रवाती परिसंचरण तक, दक्षिण गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर औसत समुद्र तल से 3.1 से 4.5 किमी के बीच स्थित बना हुआ है।

मध्यप्रदेश में पहली बार बैरियर-लेस टोलिंग का पायलट परीक्षण शुरू

भोपाल। मध्यप्रदेश में टोल व्यवस्था को अधिक आधुनिक, सुगम और निर्बाध बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा एक महत्वपूर्ण नवाचार की शुरूआत की गई है। भोपालझदेवास मार्ग के फंदा टोल प्लाजा पर प्रदेश में पहली बार बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम का पायलट परीक्षण शुरू किया गया है। इस व्यवस्था में वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी और पारंपरिक बूम बैरियर के कारण होने वाली अनावश्यक ब्रेकिंग एवं समय की बबार्दी से भी यात्रियों को राहत मिलेगी।

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारियों ने इस नवाचार और इसके

क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया का लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया। प्रस्तुतीकरण के बाद मंत्री श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में लागू किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि पायलट परीक्षण के दौरान प्राप्त परिणामों का विधिवत मूल्यांकन किया जाए और इसके आधार पर इसे प्रदेश में वृहद स्तर पर लागू करने की कार्ययोजना तैयार की जाए।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में सड़क अधोसंरचना के विकास के साथ आधुनिक तकनीक के उपयोग को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सड़क निर्माण और यातायात व्यवस्था का उद्देश्य केवल बेहतर सड़क उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित, सुगम और समय की बचत वाली यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना भी है। बैरियर-लेस टोलिंग इसी सोच के अनुरूप किया जा रहा एक महत्वपूर्ण नवाचार है।

आयुष्मान भारत निरामयम योजना में अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई

भोपाल। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन तथा पात्र हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश में योजना से संबद्ध अस्पतालों की निरंतर निगरानी एवं जांच की जा रही है। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अस्पतालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। जनवरी 2026 से अब तक प्रदेश में 83 अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

मध्यप्रदेश की सुमन पंचायत पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू

भोपाल। मध्यप्रदेश की मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए संचालित नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहचान मिली है। लखनऊ में आयोजित नेशनल वर्कशॉप ऑन सुमन रोडमैप 2030 में सुमन (सुरक्षित मातृत्व आश्वासन) के अंतर्गत मध्यप्रदेश द्वारा विकसित सुमन पंचायत और सुमन सखी चैटबॉट को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट प्रैक्टिस एवं अन्य राज्यों में लागू किए जाने वाले स्केलेबल इंटरवेंशन के रूप में मान्यता मिली है। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह मध्यप्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखते हुए गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को सुरक्षित, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ समुदाय की भागीदारी, डिजिटल तकनीक और डेटा आधारित मॉनिटरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सुमन पंचायत और सुमन सखी चैटबॉट जैसे नवाचार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन पहलों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने, सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने में सहायता मिल रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की इन पहलों का राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में स्वीकार किया जाना प्रदेश में किए जा रहे नवाचारों की प्रभावशीलता का प्रमाण है।

राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एमपी के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन

भोपाल। पंजाब के लुधियाना स्थित गुरु नानक स्टेडियम में 01 से 03 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही 21वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 में मध्यप्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में अकादमी के खिलाड़ियों ने अब तक दो स्वर्ण और एक कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। इनमें कृष्ण चंद्र ने जैवलिन थ्रो में नया मीट रिकॉर्ड कायम कर स्वर्ण पदक जीतकर विशेष उपलब्धि हासिल की।

जैवलिन थ्रो में कृष्ण चंद्र का नया मीट रिकॉर्ड

प्रतियोगिता के बुधवार शाम आयोजित मुकाबलों में बॉयज जैवलिन थ्रो स्पर्धा में मध्यप्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी कृष्ण चंद्र ने 79.92 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रतियोगिता का नया मीट रिकॉर्ड भी कायम किया। कृष्ण चंद्र के शानदार प्रदर्शन से पहले इस स्पर्धा का मीट रिकॉर्ड 77.41 मीटर था, जो रोहित यादव ने वर्ष 2018 में बनाया था। कृष्ण चंद्र ने 79.92 मीटर का प्रदर्शन कर पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

हेप्टाथलॉन में नागर सिंह कनेश ने जीता स्वर्ण

हेप्टाथलॉन स्पर्धा में अकादमी के खिलाड़ी नागर सिंह कनेश ने 4812 अंकों के शानदार प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नागर सिंह ने स्पर्धा के विभिन्न इवेंट्स में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया और मध्यप्रदेश

को स्वर्णिम सफलता दिलाई।

1000 मीटर में रंगलाल डोडिया ने जीता कांस्य

वहीं 1000 मीटर स्पर्धा में अकादमी के खिलाड़ी रंगलाल डोडिया ने 2 मिनट 26.83 सेकंड के शानदार समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। रंगलाल ने अपनी गति और दमदार प्रदर्शन के साथ स्पर्धा में तीसरा स्थान प्राप्त किया।

राष्ट्रीय मंच पर मध्यप्रदेश की खेल प्रतिभा ने छोड़ी छाप

21वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन उनकी मेहनत, अनुशासन, निरंतर अभ्यास और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। विशेष रूप से जैवलिन थ्रो में नया मीट रिकॉर्ड कायम करना प्रदेश की उभरती एथलेटिक्स प्रतिभाओं के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों द्वारा हासिल की जा रही यह सफलता मध्यप्रदेश में विकसित हो रही खेल संस्कृति और अकादमियों में खिलाड़ियों को मिल रहे उच्चस्तरीय प्रशिक्षण का परिणाम है।

खेल मंत्री श्री सारंग ने दी बधाई

सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण एवं कांस्य पदक जीतने वाले नागर सिंह कनेश, कृष्ण चंद्र एवं रंगलाल डोडिया को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और कृष्ण चंद्र द्वारा नया मीट रिकॉर्ड कायम किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों की यह उपलब्धि प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।